



कानपुर नगर निगम

दिनांक 28.12.2019 दिन शनिवार को आहूत स्थगित सदन की बैठक का कार्यवृत्त एवं पुनः
दिनांक 08.01.2020 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित
सभागार में सम्पन्न हुई, बैठकों का कार्यवृत्त

स्थान: नगर निगम सभागार, मोतीझील, कानपुर



कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या :- डी/५४२/सचिव (न०नि०)/2019-20

दिनांक :- ०७-०२-२०२०

सेवा में,

मा० श्री/श्रीमती.....

पार्षद वार्ड सं०...../पदेन सदस्य.....

महोदय/महोदया,

नगर निगम सदन की दिनांक 28.12.2019 दिन शनिवार को आहूत बैठक जो स्थगित की गयी थी की कार्यवृत्ति तथा दिनांक 28.12.2019 दिन शनिवार को स्थगित सदन की बैठक, जो दिनांक-08.01.2020 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त, आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 26 तक व
कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 42 तक।

सचिव
नगर निगम, कानपुर

प्रतिलिपि :-

- 1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
- 2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) महोदय को सूचनार्थ।
- 3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम, कानपुर

नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में दिनांक- 28.12.2019 दिन शनिवार की स्थगित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/अध्यक्ष	22. श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
2. श्री रमेश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	23. श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद/सदस्य
3. श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद/सदस्य	24. श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद/सदस्य
4. कु० लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	25. श्री शरद प्रकाश मिश्रा	पार्षद/सदस्य
5. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद/सदस्य	26. श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद/सदस्य
6. श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	27. श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
7. श्रीमती आरती गौतम	पार्षद/सदस्य	28. श्री रमेश बाजपेई	पार्षद/सदस्य
8. श्री अवनीश खन्ना	पार्षद/सदस्य	29. श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद/सदस्य
9. श्री अजीत	पार्षद/सदस्य	30. कु० विधि राजपाल	पार्षद/सदस्य
10. श्री मदन बाबू	पार्षद/सदस्य	31. श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद/सदस्य
11. श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य	32. श्री अशोक पाल	पार्षद/सदस्य
12. श्री सौरभ देव	पार्षद/सदस्य	33. श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद/सदस्य
13. श्री राकेश कुमार	पार्षद/सदस्य	34. श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद/सदस्य
14. श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	35. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद/सदस्य
15. श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद/सदस्य	36. श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद/सदस्य
16. श्रीमती राधा देवी	पार्षद/सदस्य	37. कु० कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद/सदस्य
17. श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद/सदस्य	38. श्रीमती नेहा यादव	पार्षद/सदस्य
18. श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	39. श्री विजय कुमार	पार्षद/सदस्य
19. श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य	40. श्री दिनेश तिवारी	पार्षद/सदस्य
20. श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद/सदस्य	41. श्रीमती प्रभा सिंह चौहान	पार्षद/सदस्य
21. श्रीमती कविता सिंह	पार्षद/सदस्य	42. श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य

43. श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद/सदस्य	68. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद/सदस्य
44. श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद/सदस्य	69. श्रीमती सुधा	पार्षद/सदस्य
45. श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	70. श्री यशपाल सिंह	पार्षद/सदस्य
46. श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद/सदस्य	71. श्री विकास जायसवाल	पार्षद/सदस्य
47. श्री विजय यादव	पार्षद/सदस्य	72. श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद/सदस्य
48. श्री अनिल वर्मा	पार्षद/सदस्य	73. श्रीमती शशी साहू	पार्षद/सदस्य
49. श्री नूर आलम	पार्षद/सदस्य	74. श्री सन्तोष साहू	पार्षद/सदस्य
50. श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद/सदस्य	75. श्री राशिद आरफी	पार्षद/सदस्य
51. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	76. श्रीमती अल्पना जायसवाल	पार्षद/सदस्य
52. श्री मो० आमिर खान	पार्षद/सदस्य	77. श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	पार्षद/सदस्य
53. श्री जितेन्द्र	पार्षद/सदस्य	78. श्रीमती सुमन त्रिवेदी	पार्षद/सदस्य
54. श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद/सदस्य	79. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर	पार्षद/सदस्य
55. श्री सौरभ तिवारी	पार्षद/सदस्य	80. श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद/सदस्य
56. श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद/सदस्य	81. श्री गुरु नारायण गुप्ता	पार्षद/सदस्य
57. श्री नीरज बाजपेई	पार्षद/सदस्य	82. श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद/सदस्य
58. श्रीमती सीमा सचान	पार्षद/सदस्य	83. श्री प्रमोद जायसवाल	पार्षद/सदस्य
59. श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद/सदस्य	84. श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य
60. श्रीमती दीपा	पार्षद/सदस्य	85. श्रीमती जरीना खातून	पार्षद/सदस्य
61. श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद/सदस्य	86. श्री दीपक शर्मा	पार्षद/सदस्य
62. श्री अरविन्द यादव	पार्षद/सदस्य	87. श्री कौसर अली	पार्षद/सदस्य
63. श्रीमती चन्द्रावती	पार्षद/सदस्य	88. श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद/सदस्य
64. श्री लियाकत अली	पार्षद/सदस्य	89. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद/सदस्य
65. श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद/सदस्य	90. श्रीमती शाहीन खातून	पार्षद/सदस्य
66. श्री राजीव सेतिया	पार्षद/सदस्य	91. श्री मन्नु रहमान	पार्षद/सदस्य
67. श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	92. श्री मो० आरिफ	पार्षद/सदस्य

93. श्री शिवम दीक्षित	पार्षद/सदस्य
94. श्री राशिद महमूद	पार्षद/सदस्य
95. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद/सदस्य
96. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद/सदस्य
97. श्री अश्वनी चड्ढा	पार्षद/सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4. श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
5. श्री रमेश कुमार निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. श्री कैलाश सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
7. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'

वन्देमातरम् गायन के पश्चात् पूर्वान्ह 11:15 बजे कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनट के लिये स्थगित हुई।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् पूर्वान्ह 11:45 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त श्री अमृतलाल बिन्द को एजेण्डानुसार बैठक संचालन हेतु निर्देशित किया, तदनुक्रम में अपर नगर आयुक्त ने श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू" कार्यकारिणी समिति के उपसभापति के सभागार में अनुपस्थित होने के कारण मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को एजेण्डा के बिन्दु संख्या-1 में अंकित नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट के तखमीनो से सदस्यों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट की प्रतियाँ वितरित कराते हुये सदन पटल पर प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव संख्या -58

दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव -89 (1) नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019-20 का मूल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह लगभग 900.00 लाख (09 करोड़) की धनराशि नगर निगम निधि से जोड़ने हेतु अधिकांशियाँ/कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन में भूतलान की जाती है। जिस कारण नगर निगम निधि से होने वाले विकास कार्यों पर दृष्टाभाव पड़ रहा है तथा चाहते हेतु भी निगम नगर निगम निधि से विकास कार्य करने में

(धनराशि करोड़ में)

बढ़कर 145.00 करोड़ हो गया है तथा 31 मार्च तक कुल 155.00 करोड़ सम्भावित है।

2017-18 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 81.00 करोड़ रुपये अधिदान पर अधिक व्यय किया है जो वार्षिक वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 34.00 करोड़ रुपये अधिदान पर अधिक व्यय किया था तथा वित्तीय वर्ष वीरे की भांति है। वित्त तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति से सुस्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि लगातार कम हो रही है जबकि अधिदान पर व्यय लगातार 2. महत्वपूर्ण आप सभी अवगत है कि राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह प्राप्त होने वाली धनराशि (को 2120 लाख) नगर निगम की आवश्यकता को देखते हेतु ऊँच के मुँह में

लागत यह है कि महंगाई की दर में गिरावट के बावजूद भी हमने बजट की धनराशि में बढ़ोतरी कर कानपुर के विकास में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

साल के निम्न स्तर पर थी। आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही में खुरदा महंगाई 2.8 फीसदी के आस पास रह सकती है। सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) में मालवारा दिनांक 12 फरवरी 2019 को ही यह आंकड़ा जारी किया है। दिसंबर 2018 में महंगाई 2.19 फीसदी पर रही थी, जो डेढ़ हेतु 2.05 फीसदी पर आ गयी है। पिछले साल से तुलना करे तो महंगाई एक तिहाई रह गयी है। खुरदा महंगाई जनवरी 2018 में 5.07 फीसदी थी। केन्द्रीय कानपुर की तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद गत वर्ष से 3003.33 लाख (33 करोड़ 03 लाख 33 हजार) अधिक है। खुरदा महंगाई जनवरी 2019 में और लुकेत वित्तीय वर्ष 2019-20 का मूल बजट 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो नगर निगम

23 हजार) कुल रूपया 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) का मूल बजट तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हूँ -

83 हजार) के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 125289.60 लाख (1252 करोड़ 89 लाख 60 हजार) अन्तिम अवधि 22978.23 लाख (229 करोड़ 78 लाख करोड़ 35 लाख 70 हजार) व प्राथमिक अवधि रूपया 32732.13 लाख (327 करोड़ 32 लाख 13 हजार) कुल रूपया 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख लेखाधिकारी, नगर निगम कानपुर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कुल आय 115535.70 लाख (1155 सभी विद्वतजनों के समक्ष नगर आयुक्त महोदय के मार्ग दर्शन तथा नगर निगम कानपुर के विभागाध्यक्षों से किये गये विचार विमर्श के पश्चात् में मुख्य वित्त एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि माननीय सभापति जी, कार्यकारिणी के मा0 सदस्य गण, आप

निगम असुविधा महसूस कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो न तो पूर्व में पूर्ण हुये कार्यों का भुगतान हो पायेगा और न ही नये कार्य हो पायेंगे और अंततः नगर निगम की छवि धूमिल होगी। चौथी शताब्दी ई0 पूर्व के महान चिन्तक कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थ के बिना कोई राज्य चलना असंभव है। आय के अनुसार खर्च करना चाहिये। फिजूलखर्ची बर्बाद कर देगी। अतः आवश्यकता इस बात की है, कि हमें नगर निगम के राजस्व की वृद्धि में न केवल मिलजुल कर ठोस सामूहिक प्रयास करने होंगे बल्कि एक जुनून जगाना होगा क्योंकि कहते हैं –

मंजिल यू ही नहीं मिलती दोस्त ,एक जुनून जगाना पड़ता है।

पूछां चिड़िया से घोसला कैसे बनता है ,बोली तिनका – तिनका उठाना पड़ता है।

बजट में प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2019 तक सम्पत्ति कर से नगर निगम की वास्तविक आय 8265.58 लाख (82 करोड़ 65 लाख 58 हजार) ही हो सकी है जो मार्च तक लगभग 11500 लाख (115.00 करोड़) सम्भावित है। इतनी धनराशि तो वेतन एवं पेंशन की प्रतिपूर्ति में ही खप जायेगी फिर विकास कार्य एवं अन्य आवश्यक व्यय कैसे होंगे यह सोचने का विषय है। आने वाले वित्तीय वर्ष में मंहगाई भत्ता आदि की बढ़ोत्तरी होने से अधिष्ठान व्यय बढ़ना ही है। अतः उसी अनुपात में हमें अपने सम्पत्ति कर की वसूली में वृद्धि करनी होगी , अन्यथा कानपुर की भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। यहाँ हमें शायर मुजफ्फर रज़मी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है –

कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नज़रो में ,

लम्हो ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी है।

3 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली अपर्याप्त धनराशि तथा आवश्यकता के सापेक्ष कम वसूली की प्रकृति के दृष्टिगत आवश्यकता इस बात की है कि सड़क अनुरक्षण ,नाला/नाली अनुरक्षण जैसे बड़े कामों को 14 वां वित्त आयोग की धनराशि से कराने को प्राथमिकता दी जाये इसी कारण आगामी वित्तीय वर्ष के मूल बजट में चालू वित्तीय वर्ष से उक्त मदों में क्रमशः रूपया 5.0 करोड़ व रूपया 1.5 करोड़ कम की गयी है तथा नगर निगम की वर्तमान आवश्यकता जहरीली प्राण वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु उद्यानों का रख रखाव /वृक्षारोपण /हरित क्षेत्र के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के प्राविधानित 3.0 करोड़ के अनुमानित बजट को बढ़ाकर 10.00 करोड़ किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु खेल के मैदानों /क्रीड़ा स्थलों के रख रखाव एवं खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु चालू वित्तीय वर्ष की प्राविधानित धनराशि रूपया 25.00 लाख को बढ़ा कर आगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 1.00 करोड़ प्रस्तावित है। आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को दृष्टिगत रखते हुये कान्हा गौशाला एवं बे-सहारा पशु आश्रय योजना का एक नया तखमीना बनाकर आगामी वित्तीय वर्ष में रूपया

हमारा दावा है, हर घर को जगमगायेँ ,

अप्रसर रहते हुए न केवल राज्य में बल्कि देश में भी अपना परचम फहरा सके। आप सभी महानुभावों की तरफ से —
 सामान्य के हित में विकास कार्यों की गंगा बहती रहे जिसके पवित्र जल से अभिसिद्धित जन सामान्य की दुआओं से नगर निगम पूर्व की शक्ति प्रगति के पथ पर किये जाने का बजट अनुमान तैयार किया गया है ताकि बड़े कार्य यथा सम्भव इन मर्तों से सम्पादित हो सके तथा निधि पर अनावश्यक व्यय भार न पड़े। जन कुल प्राप्त धनराशि 987.40 लाख (9 करोड़ 87 लाख 40 हजार) के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष में रुपया 3000.00 लाख (30 करोड़) विकास कार्य हेतु व्यय में रुपया 15000.00 लाख (150 करोड़) विकास कार्य हेतु व्यय किये जाने का बजट अनुमान तैयार किया गया है। अवस्थापना निधि में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल धनराशि 9697.66 लाख (96 करोड़ 97 लाख 66 हजार) के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष

तकाला है वकल का कि लोकन से जुडो
 कहाँ तक चलोगे किनारे

4 वित्तीय प्रश्नान्तियों के बाबजूद जहाँ प्रदेश के अन्य नगर निगमों में कई कई माह से वेतन एवं पेंशन के भुगतान लम्बित होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो रहा है वहीं हमें यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि अभी तक नगर निगम कानपुर में ऐसी कोई विषम स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गयी है और आगे भी सख्त आधिकारियों/कर्मचारियों के देय भुगतान कर नगर निगम कानपुर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाये रखने का पूरा प्रयास किया जायेगा। लेकिन हमें इस सच्चाई से भी मुंह नहीं फेर लेना है कि कितनाहाल हमारी साथी ऊर्जा वेतन एवं पेंशन की प्रतिपूर्ति करने में ही खर्च हो रही है।
 लक्ष्य रखा गया है।

का लक्ष्य बढ़ाने का प्रभाव व्यय पक्ष पर पड़ना स्वाभाविक था इसलिए बजट प्राविधान अधिक न बढ़ाते हुए आर्थिक आय से लम्बित देयताओं की प्रतिपूर्ति का प्रस्तावित है जो (168 करोड़ 01 लाख 50 हजार) व्यवहारिक लक्ष्य से बहुत कम है आवश्यकताओं के दृष्टिगत हमें इस लक्ष्य के पार जाना होगा। बजट में आय नगर निगम की लम्बित देयताओं के दृष्टिगत करों से आय का लक्ष्य चार्लू वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 13.00 करोड़ अधिक कर्मचारियों के वेतन तथा इस कार्य में लगाये गये वाहनों के रख रखाव एवं इंधन का प्रशक से हिसाब रखने हेतु नये लखनीनों का सृजन किया गया है।
 10.00 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइड लाइन्स के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यरत सविदा/आउटसोर्स

दियों की लौ को, हवाओं से हम बचायेंगे।
स्वर्ग उतरेगा एक रोज़, कानपुर की धरती पर,
जो कोई कर नहीं पाया, वह कर दिखायेंगे

6. इन्ही विशेषताओं के साथ नगर निगम कानपुर का मूल बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
कृपया विचारोपरान्त अनुमोदन देने की कृपा की जाये।

धन्यवाद।

नगर निगम कानपुर
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2017-18	मूल/पुनरीक्षित धनराशि 2018-19	वास्तविक आय जनवरी 2014 तक	वास्तविक आय जनवरी 2019 तक	प्रस्तावित धनराशि 2019-20
	Revenue Income		राजस्व आय						
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	13285.50	15501.50		8502.18	16801.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के आधीन आय	3	0.57	4.00		2.57	4.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	107.45	170.50		94.50	170.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	1094.22	2379.00		1894.46	2549.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	121.90	227.00		49.47	227.00

1701	Income from Investments	1701	निवेशों से आय	5	0.00	6.00	0.00	6.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	409.47	405.00	294.52	405.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	238.23	462.10	270.10	462.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	स्वायत्त अर्पण एवं अर्पण	6	30468.46	31202.00	22071.09	31277.00
	TOTAL (A)		योग (अ)	6	45725.80	50357.10	33178.89	51902.10
	Capital Income		पूंजीगत आय	-				
3111	Farmed Funds	3111	काँच किसान निधि	-				
3111	Finance Commission: Forteenth	3111	बिना आयोग : चौदहवाँ	6	13292.99	13100.00	5134.80	13100.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	आयोजना निधि	6	3063.17	4050.00	1106.22	4050.00
3111	Other Farmed Fund	3111	अन्य कायदाबद्ध निधि	6-7	12305.34	14635.50	884.49	3895.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	3.00	0.00	3.00
	TOTAL B		योग (ब)	7	28661.50	31792.50	7125.51	21052.00
	Reserve Fund (NNURM)		निधि फंड					
			(नॉन-फंडेड-एग्रीमेंट/अन्य)					
3311	Unsecured Loans	3311	अन्य सुरक्षित धनिक निधि	7	0.00	5200.00	0.00	5200.00
3111	JNNURM Scheme	3111	जी.एन.यू.एम. स्कीम/अन्य	7-8	323.85	37381.60	3680.70	37381.60
	TOTAL C-		योग (स)	8	323.85	42581.60	3680.70	42581.60
	Total Revenue, Capital & Reserve		कुल राजस्व, पूंजीगत एवं निधि	8	74711.14	124731.20	43985.11	115535.70
	Fund Income (A+B+C)		फंड आय (अ+ब+स)					
4502	Opening Balance	4502	प्रारंभिक अवधि-	8	29372.04	12469.40	36729.81	32732.13
	Grand Total		प्रारंभिक	8	104083.19	137200.60	80714.92	148267.83

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2017-18	मूल/पुनरीक्षित धनराशि 2018-19	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	वास्तविक व्यय जनवरी 2019 तक	प्रस्तावित धनराशि 2019-20
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय						
2101	Establishment Expenses	2101	अविष्टान व्यय	9	36010.85	40420.00		31278.89	40455.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	1543.57	2037.00		947.64	2257.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-12	8946.61	10391.00		4320.08	12496.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	399.16	458.00		0.45	458.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	293.66	1340.00		106.66	1040.00
	TOTAL -D-		योग (द)	13	47193.86	54646.00		36653.71	56706.00
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय						
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ						
3111	Finance Commission: Forteenth	3111	वित्त आयोग : चौदहवीं	14	7777.48	16500.00		8211.36	16500.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	2280.72	4000.00		2300.44	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	11732.00	15131.50		1045.23	5516.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00		0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00		0.00	32.00
	Total -E-		योग (य)	15	21790.21	35667.50		11557.03	26052.00
	Total -(D+E)		योग (द+य)	15	68984.06	90313.50		48210.74	82758.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0/अमृत)						
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	5200.00		0.00	5200.00
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम/अमृत योजना	15	105.65	37331.60		3725.18	37331.60

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि बजट में नगर निगम की जो आय दिखाई गई है, क्या वह वास्तविक आय है या उसमें ओटीएस योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि भी शामिल है। बजट सत्र व्यतीत हो चुका है, तो ऐसे में क्या अब बजट सदन में लाना उचित है ? इस समय तो सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि महानगर की समस्याओं से सम्बन्धित सभी विषयों पर चर्चा की जाये, किन्तु कुचर्चा न की जाये। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से कहा है कि एक-एक विषय पर जवाब दिया जायेगा। कृपया शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलने दिया जाये ताकि सभी विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके।

श्री सौरभ देव ने कहा कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी यह बताये कि बजट में लॉयबिलिटी कितनी है ? ओटीएस में कितनी धनराशि जमा हुई है ? इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या वास्तविक आँकड़े दिसम्बर तक नहीं मिल सके।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2017-18 की आय-व्यय को संज्ञान में लेते हुये तथा वर्ष 2018-19 की जनवरी तक की आय-व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 का (अनुमानित आय-व्यय) बजट तैयार किया गया है, जिसमें आय-व्यय की तख्मीनें अंकित है। सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया उसे देख लिया जाये यदि कोई विशेष जानकारी चाहिये तो मेरे कार्यालय में सादर आमंत्रित है।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि ओटीएस द्वारा की गयी वसूली गयी समस्त धनराशि का विवरण प्रश्नकर्ताओं को उपलब्ध कराएं।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा थी कि महानगरों को चट्टामुक्त, गड्ढामुक्त किया जाये, यह क्यों नहीं हुआ ? स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत बनवाये गये शौचालय आज भी अधूरे पड़े हैं, परन्तु पूर्ण दिखा दिये गये। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नगर निगम का स्वास्थ्य व अभियन्त्रण विभाग द्वारा नाले साफ नहीं कराये गये, जिसके कारण पिछली बरसात में शहर जलमग्न हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मेरे वार्ड में 03 गाड़ियाँ दिये जाने हेतु कहा गया था, किन्तु इनके द्वारा मेरे वार्ड में एक ही गाड़ी दी गई, ऐसा क्यों ?

सभापति ने सभी सदस्यों से सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सदन सही ढंग से संचालित हो, इसलिये सभी सदस्य कार्यसूची के एक-एक बिन्दु पर चर्चा करें।

श्री स्वर्ण सिंह, सहचक्र नगर आयुक्त ने अवगत करवाया कि नगर निगम अधिनियम-1959 के अन्तर्गत किसी भी विज्ञापन एजेंसी को दो वर्ष से अधिक विज्ञापन हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती है, किन्तु यह अनुबन्ध पी०पी०पी० पर आधारित है।

पी०पी०पी० मॉडल पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
 हो रही है, कंपया इसकी भी जाँच कराई जाये। साथ ही यह भी अवगत कराए कि क्या बिना मा० सदन/कार्यकारिणी की अनुमति के बिना कराया जाये क्योंकि वहाँ पर पदस्थ एक अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर कई वित्तीय अनियमिततायें प्रकार भरे वाह के अन्तर्गत स्थित पालिका स्टैडियम में पिछले वर्ष कितनी आय हुई और उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ, इससे मुझे अवगत द्वारा कम्पनी से साँट-गाँट करके अनियमितता करते हुए यह अनुबन्ध किया गया है, उसके विकसित करने कायदाही की जानी चाहिये। इसी अधिनियम-1959 की धारा-305 के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा अधिनियम 02 वर्ष का अनुबन्ध किया जा सकता है, ऐसे में जिस अधिकारी अभी नगर निगम के किसी अधिकारी द्वारा एक विज्ञापन एजेंसी से 25 वर्षों का अनुबन्ध कर लिया गया है, जबकि नगर निगम श्री सौरभ देव ने कहा कि अध्यक्ष महोदय में अवगत करना चाहता हूँ कि विज्ञापन विभाग में बहुत अनियमिततायें की जा रही है।

इसी के अन्तर्गत में विज्ञापन कर की बजाय रथल किया जा लगे करेंगे।
 अपर नगर आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि विज्ञापन कर की वसूली नहीं की जायेगी।

को काई आय नहीं है, फिर बजट में विज्ञापन मद में यह आय कहां से दर्शायी गयी है।
 बैठक में जब नगर आयुक्त जी से विज्ञापन के सम्बन्ध में पूछा था, तब नगर आयुक्त जी द्वारा बताया गया था कि विज्ञापन से नगर निगम वर्ष 17-18, 18-19 में ₹० 500.00 लाख व वर्ष 2019-20 की प्रस्तावित ₹० 500.00 लाख दर्शाई गई है। मैंने कार्यकारिणी समिति की श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि विज्ञापन में वार्षिक आय

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि यह बजट का विशेष सदन है, इसलिये ऑटोटी०एस० पर अलग से चर्चा कर ली जायेगी।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि इसके पूर्व में भी इसीप्रकार विज्ञापन हेतु पी0एस0आई0टी0 को दिया गया था, जिसकी पत्रावली आज तक उपलब्ध नहीं है। सेलवेल कम्पनी को जो स्थल नगर निगम द्वारा दिये गये हैं, क्या वह उन स्थलों पर नगर निगम की शर्तों का पालन कर रही है। यहाँ पर अनियमिततायें की जा रही हैं। इस अनुबन्ध को निरस्त कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में परीक्षण कर जाँच आख्या उपलब्ध कराएं।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि मैंने पूर्व में ही प्रस्ताव दिया था कि कानपुर महानगर को विज्ञापन मुक्त कर दिया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जब विज्ञापन से वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है और 07 वर्षों से विज्ञापन नियमावली नहीं बन सकी, न ही आपत्तियों पर चर्चा हुई, तो बजट में विज्ञापन मद में जो आय दर्शाई गई है, वह किससे जमा कराई गई है।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जिन विज्ञापन एजेन्सियों ने अपनी स्वेच्छा से विज्ञापन कर जमा किया है, उनसे जमा करा लिया गया है।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि आपने अभी कहा कि जिन विज्ञापन एजेन्सियों ने अपनी मर्जी से विज्ञापन कर जमा किया है, उनसे जमा करा लिया गया है। यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन कर की वसूली पर रोक लगा दी गई है, तो क्या यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं है ? यदि बाद में विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस किया जाता है, तो बजट में इस मद में दर्शाई गई आय शून्य हो जायेगी ? अपर नगर आयुक्त जी आप मा0 सदन व कार्यकारिणी के आदेशों को दबा देते हैं, यह मा0 सदन व कार्यकारिणी की अवहेलना है। अध्यक्ष महोदय अपर नगर आयुक्त जी के ऊपर कार्य का अधिक भार है, कृपया इनका कुछ कार्यभार दूसरे अधिकारियों को भी दे दिया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापन में की गई अनियमितताओं के लिये अधिकारियों एवं पार्षदों सहित एक कमेटी बनाई जाये और जाँच के उपरान्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। यह भी बताया जाये कि अधिनियम के विपरीत एक कम्पनी से 25 वर्ष का अनुबन्ध कैसे किया गया।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि इस निर्णय को निरस्त किया जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व की कार्यकारिणी समिति की बैठक में ₹0 10.00 लाख तक के कार्यों को ई-टेंडरिंग से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु संज्ञान में आया है कि ₹0 10.00 लाख तक के कार्यों को भी ई-टेंडरिंग से कराये जाने की तैयारी हो रही है, यह किससे आदेश से और क्या हो रहा है ? क्या कार्यकारिणी व सदन से भी बढकर कोई सर्वोच्च संस्था है ? यह भी स्पष्ट करें कि उपरोक्त दशमिं गये निर्णय "नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों हेतु आमन्त्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी" क्या विधि संगत है ?

श्री महेंद्र पाण्डेय ने कहा कि उपरोक्त निर्णय जिसमें अभियन्तण विभाग के कार्यों में ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा वाले जाने पर निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी, जबकि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है।

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों के वाई क्षेत्रों से एक-एक पाक तथा एक महापौर जी के निर्देशानुसार इस प्रकार कुल 13 पाक अमृत योजना के अन्तर्गत विकसित कराये जाने एवं नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों हेतु आमन्त्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त माने जाने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों के वाई क्षेत्रों से एक-एक पाक तथा एक महापौर

पर ₹0 25.00 लाख की आय दशाई गई है, अवगत कराये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अग्र नगर आयुक्त ने प्रस्ताव सं-2 पर विचार विमर्श हेतु सदस्यों से अनुरोध किया, जिस पर श्री हजी सुहेल अहमद ने कहा कि अग्र नगर आयुक्त जी आप सदन को गुमराह कर रहे हो। आप बिना सदन की सहमति लिये बजट पास करते हुये अगले प्रस्ताव पर आ गये, मैं पूछना चाहता हूँ कि केशीनाथ के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो आप द्वारा बजट में केशीनाथ के मद में किस आधार

पा रहा है, इससे नगर निगम को लगभग 04-05 करोड़ की वित्तीय हानि हो रही है। यही स्थिति विज्ञापन पटों की भी है।

श्री शरद मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कानपुर महानगर के अन्तर्गत यूनियोनल पर विज्ञापन करते हुये विज्ञापन एजेंसियाँ द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ताओं से धनराशि की वसूली कर रहे हैं, किन्तु जी0एफ0सी0 के कारण नगर निगम उनसे वसूली नहीं कर

अपर नगर आयुक्त प्रथम ने सदस्यों को अवगत कराया कि इस निर्णय पर चर्चा हुई थी, यह कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुख्य अभियन्ता "सिविल" ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि यह निर्णय वित्तीय नियमों के विपरीत एवं विधिसंगत नहीं है। अतः इसे निरस्त माना जाये।

..... अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त माने जाने से पूर्व मा0 पार्षदों एवं अधिकारियों की एक कमिटी बनाकर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।

..... सर्वसम्मति से नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट में आय के पक्ष में रू0 115535.70 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0 32732.13 लाख इस प्रकार कुल रू0 148267.83 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 125289.60 लाख तथा अन्तिम अवशेष रू0 22978.23 इस प्रकार कुल रू0 148267.83 लाख दर्शायी गई धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या -59

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-213 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

कानपुर नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट के आय व्यय विवरण में आवंटित धनराशि के अर्न्तगत दिनांक 29 अक्टूबर 2019 को वास्तविक आय व्यय के अनुसार कार्य हित में निम्न मद में 31 मार्च 2020 तक आय एवं व्यय में अनुमानित आवंटित धनराशि को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है जो निम्नवत है :-

आय पक्ष—

धनराशि लाख में।					
क्रमांक	मद शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट में आवंटित	दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तक आय	संशोधित बजट धनराशि

उपरोक्तानुसार उल्लिखित मद मे आवंटित धनराशि संशोधित किए जाने की स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ मा० कार्यारिणी समिति के समक्ष प्रसत्तु है। यह भी निवेदित है कि उक्त संशोधन के फलस्वरूप मूल बजट में प्रस्तावित कुल आय एवं कुल व्यय की धनराशि यथावत बनी रहेगी।

..... वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट के उपरोक्तानुसार मदों की संशोधित धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-60

दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई मा० कार्यारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव -89 (2) जलकल विभाग का वार्षिक बजट वर्ष 2019-20 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा० सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :-

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019-20

(रु० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2017-18	प्रस्तावित आय 2018-19	वास्तविक आय दिसम्बर, 2018	प्रस्तावित आय 2019-20
अ-		राजस्व आय -				
1100201		जलकर	5714.80	6700.00	3731.25	7530.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1668.10	2260.00	752.60	2410.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2116.87	2970.00	1073.08	3050.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	17.66	30.00	13.72	30.00
1408001		अधिभार	3.31	10.00	0.16	10.00
1401502		नियमितीकरण	10.50	20.00	5.10	20.00
1401401		विकास शुल्क	125.76	120.00	69.80	120.00
योग राजस्व-			9657.00	12110.00	5645.71	13170.00
ब-		असंचालन आय -				
3111301		डिपाजिट कार्य	727.77	500.00	1166.62	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	-	3600.00	-	3600.00

3311001	घ-	कुल आय --	10384.77	16210.00	6812.33	17270.00
		अथ से प्राप्त	-	-	-	-
		योग--(अ+ब+घ)	10384.77	16210.00	6812.33	17270.00
		प्रारम्भिक अंश	6388.35	2675.00	4065.49	2372.00
		प्रशुद्धि	16773.12	18885.00	10877.82	19642.00

जनकल विभाग, नगर निगम, काजपुर
प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019-20

(रु० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	भर विवरण	प्रस्तावित आय 2017-18	प्रस्तावित आय 2018-19	प्रस्तावित आय दिसम्बर, 2018	प्रस्तावित आय 2019-20
----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

अ- अविधान व्यय -						
2101001	1	अविधान व्यय	9132.64	10835.00	6823.17	10405.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	259.48	3000.00	6.00	3600.00
2303004	3	पूर्विका	351.82	600.00	333.25	700.00
2308007	4	अन्य व्यय	39.47	75.00	42.92	75.00
2305006	5	रख-रखाव व्यय	777.85	1185.00	654.68	1390.00
2208003	6	जगरल टैक्स	301.49	250.00	0.00	300.00
योग संवर्धन व्यय-			10862.75	15945.00	7860.02	16470.00

ब- संवर्धन व्यय -						
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	-	20.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कंप्यूटर क्रय	-	10.00	-	10.00
4105001	4	वाहन, टैक्टर, टैकर क्रय	-	0.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं मर्म	-	10.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूर्वागत व्यय	-	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकाय विछाना (जल/सीवर)	-	10.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प ड्रिपिंग	-	0.00	-	0.00

4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-	10.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
3111301	11	डिपॉजिट कार्य का भुगतान	1844.88	500.00	1195.44	500.00
योग असंचालन व्यय-			1844.88	568.00	1195.44	568.00
कुल योग (अ ब) व्यय			12707.63	16513.00	9055.46	17038.00
अन्तिम अवशेष			4065.49	2372.00	1822.36	2604.00
महायोग			16773.12	18885.00	10877.82	19642.00

..... सर्वसम्मति से जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 के मूल बजट के आय पक्ष में ₹0 17270.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष ₹0 2372.00 लाख इस प्रकार कुल ₹0 19642.00 लाख तथा व्यय पक्ष में ₹0 17038.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष ₹0 2604.00 लाख इस प्रकार कुल ₹0 19642.00 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या -61

प्रस्ताव

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या- 1229/3/प दिनांक 10.12.2019 को सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

कानपुर नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं(जैसे रोड, नाली, मार्ग प्रकाश, सफाई इत्यादि) को नागरिकों को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने का अभियान सम्प्रति गतिमान है। शहर में सुनियोजित विकास कार्य तथा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा रखरखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु नगर निगम की आय का एकमात्र साधन गृहकर है।

गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः गृहकर की वसूली कुल ₹0 124.88 करोड एवं ₹0 154.55 करोड रही है, जोकि काफी कम है। वर्तमान वित्तीय में कर का लक्ष्य ₹0 220.48 करोड किया गया है। व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों के गृहकर निर्धारण के विवाद एवं उनके गृहकर के अवशेष एवं ब्याज में लगातार वृद्धि के कारण अनेक भवन स्वामी गृहकर जमा न करके विवाद करते हैं।इन मुख्य विषमताओं को समाप्त करने एवं बकाये की धनराशि को त्वरित वसूली एवं सीमित अवधि हेतु एक मुश्त सामधान योजना(ओटीएस) लागू करना प्रस्तावित है।

नगर निगम कानपुर के एक मुश्त सामधान योजना(ओटीएस) के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही होनी है :-

क.सं.	भवन का प्रकार	संख्या	अवधि	खाल	योग
1	सभी प्रकार के आवासीय	368534	39.77	21.11	60.88

(नगरपालिका-कठमाडौं)

एक भूखण्ड सामाजिक योजना (ओटीएसओ) को अन्तर्गत भवनों के उपरोक्त वर्गीकरण के नगर निगम, कानपुर का विवरण निम्नवत है :-

1. सम्पूर्ण बकामत अवधि के भीतर एकमुश्त करना होगा, परन्तु पूर्व पत्रांक 2566/3/प दिनांक 09.03.2019 द्वारा घोषित प्रस्ताव, जॉर्ज शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू कर दिया गया था उसमें जमा धनराशि को आंशिक भुगतान मानते हुये, वर्तमान से लागू एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) की कुल राशि में समायोजित करते हुये अन्तर की धनराशि जमा करा लिया जाये और उसे एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) के अन्तर्गत माना जाये।
2. यह योजना शासन द्वारा कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत संशोधित आदेश के दिनांक से 06(छः) माह के लिये प्रभावी होगी। पूर्व में शासन की प्रत्याशा में कानपुर नगर निगम द्वारा प्रभावी की गई एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) में जमा धनराशि को शासन से प्राप्त एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) का अंश माना जायेगा।
3. इस योजना के अन्तर्गत मायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से संबद्ध छात्रावास ही आवंटित होंगे। - - -
4. निजी छात्रावास पर यह योजना लागू नहीं होगी।
5. आर्टोटीओआईओ, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य है और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आवंटित है।
6. इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

क्र.सं.	भवन के प्रकार	खाल	अवधि	एक भूखण्ड सामाजिक योजना (ओटीएसओ) में प्रदान की जाने वाली छूट
1	आवासीय भवन	खाल की धनराशि पर पूर्णतया छूट	धनराशि वित्तिय वर्ष 2019-20 में शासन के आदेश के दिनांक 31.01.2020 तक 20 प्रतिशत तथा तदुपरोक्त दिनांक 01.02.2020 से 31.03.2020 तक अवधि में 10 प्रतिशत छूट प्रभावी होगी।	
2	माल एवं प्लांट की 200 वर्गफुट की छोटकर, शेष 200 वर्गफुट की इकाय	अवधि	अवधि	
3	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थानों की धारा-177 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत	अवधि	अवधि	
4	शैक्षणिक इकायों व सांख्यिकी उपक्रम	अवधि	अवधि	
5	सरकारी और अधिसरकारी कार्यालय	अवधि	अवधि	योजना मार्च 2020 तक लागू रहेगी।

उपरोक्त शासन द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है, उनके लिए यह

2	सभी प्रकार के अनावासीय(छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम-177 के खण्ड(ग) के अधीन आवकादित नहीं औद्योगिक ईकाईयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी व सार्वजनिक उपक्रम आदि सम्मिलित है)	38817	73.87	39.20	113.07
योग		404351	113.64	60.31	173.95

उपरोक्त एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू होने से जनहित में जहाँ विवादों का निस्तारण होगा वही नगर निगम कानपुर की आय में भारी वृद्धि होगी। अतएव यह योजना जनहित के साथ-साथ नगर निगम के हित में होगी। अतः उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन के स्वीकृतार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि पिछले वर्ष नगर निगम द्वारा वार्डों में कैम्प लगाकर जनता से ओ0टी0एस0 लिया गया था, किन्तु जनता को उसका लाभ न देकर दोबारा बिल में पैसा जोड़कर लिया जा रहा है। इससे उ0प्र0 सरकार एवं नगर निगम की बदनामी होती है। यह हमारी सरकार की योजना है, इसका लाभ जनता को मिलना चाहिये, परन्तु यह बताया जाये कि ओ0टी0एस0 की जमा धनराशि का क्या हुआ, जो पुनः ओ0टी0एस0 प्रस्ताव लाना पड़ा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि कहाँ खर्च हुई है, इसके सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया जाये। मैं प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी आपसे व नगर आयुक्त जी से कर रहा हूँ, इसमें किसी भी पार्षद का हस्तक्षेप उचित नहीं है। ओ0टी0एस0 से प्राप्त धनराशि को कहाँ खर्च किया गया है, कृपया अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा पूर्व के एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के स्वीकृत प्रस्ताव के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन ने नीति-नियम निर्धारित करते हुये एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) प्रारूप को बोर्ड की बैठक के माध्यम से प्रेषित करने को निर्देशित किया है। तदनुसार एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) का प्रारूप तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाना है।

..... उपरोक्तानुसार एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) प्रारूप को ध्वनिमत से पारित करते हुये उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि सदन की पहली बैठक में नगर आयुक्त जी का मैं स्वागत करता हूँ साथ ही माँग करता हूँ कि मेरे वार्ड में दुर्गा पार्क को विकसित किया जाये, क्योंकि कार्पाकारिणी में अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क को विकसित करने का

जाये, इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी तथा कानपुर महानगर को विज्ञापन मुक्त कर दिया जाये।
 नहीं की गई है। विधि अधिकारी को बुलाकर इसके सम्बन्ध में पूँछा जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय इन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करवा दें।
 जिन सभी प्रस्तावों को विधिक राय में डाल दिया गया, जो पिछले कई माह से विधिक राय हेतु पड़े हैं, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं पाठित ने कहा कि मैं कार्पाकारिणी समिति में उपसमापति था, उस समय मैंने यूनियनवार्ड वसूली-सहित 06 प्रस्ताव रखे थे।

अध्यक्ष ने कहा कि श्री महेश शुकला "दददा" सदन, उपनेता है यदि कोई शिकायत है तो मिलकर अपनी बात कर सकते हैं।

कारणों से मेरे वार्ड में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है ? अवगत कराया जाये।
 है फिर भी किन कारणों से माननीय महापौर जी द्वारा मेरे ही वार्ड की विकास कार्यों की पत्रावलियाँ पर वार्ड लिखी जा रही है ? किन
 श्री महेश शुकला "दददा" ने कहा कि हम 05 बार से पार्क निर्वाचित हो रहे हैं तथा मेरी सरकार केन्द्र, प्रदेश व नगर निगम में
 भिजवाये जाये, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करें कि मविष्य में आहत सदन की बैठक में विस्तृत जानकारी के साथ प्रतिभाग करें।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि सदन पर सदस्यों द्वारा हस्तगत पत्रों के जवाब विभागों के माध्यम से

प्रेषित किया जाये।

श्री राजेश्वर मिश्रा ने कहा कि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न किये गये हैं, उसका जवाब उनको लिखित रूप से

किया जायगा।

जिससे सीवर लाइनें बाँक होती हैं। बट्टों को महानगर से बाहर किया जाना अति आवश्यक है, प्रभावी कार्यवाही करते हुये बट्टामुक्त शहर
 अध्यक्ष ने कहा कि पूरा शहर जानवरी से पीड़ित है। महानगर में बट्टे वाले बट्टे का गोबर शीघ्र सीवर लाइनों में डाल रहे हैं,

छोड़ने हेतु ₹0 5000/- माँगे जाते हैं, यह उचित नहीं है, इसे कम किया जाना चाहिये, क्योंकि गाय माला पृथ्वीय है।

श्री कमल शुकल "बेबी" ने कहा कि आज कल नगर निगम द्वारा गाय को पकड़ कर काँची हावस में डाला जाता है और उसको

प्रस्ताव रखा गया है। हम रोज नित्य जहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं, वहाँ पर एक माली तक नहीं है। जे0टी0एन0 से कूड़ा उठान हेतु तीन गुना दर लागू किये जाने हेतु कहा गया है। मेरे क्षेत्र की जनता यूजर चार्ज देने को तैयार है, किन्तु मेरे क्षेत्र की सफाई के साथ विकास कराया जाये।

श्री राजीव सेतिया ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रष्टाचार की खबरों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। पैचवर्क, नाला सफाई इत्यादि में की गई अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई है ? अध्यक्ष महोदय मेरे वार्ड में रोड कटिंग कर क्षेत्र को खोद दिया गया है, किन्तु किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही किसी ठेकेदार की बैंक गारण्टी जप्त की गई।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि मार्गप्रकाश विभाग में सण्डे एलाउन्स के नाम पर लाखों रुपये प्रतिमाह की धाँधली की जा रही है, इसकी जाँच कराई जाये। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत रामनवमी पर रामलला मन्दिर से सवारी निकलती है। रामनवमी पर निकलने वाली सवारी का मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, कृपया सवारी के मार्ग को प्राथमिकता पर बनवा दिया जाये।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि हमारे यहाँ के अधिशाषी अभियन्ता व अन्य अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। हम पार्श्व लोग जरूरत पर ही अधिकारियों को फोन करते हैं, ऐसे में उनके द्वारा फोन न उठाया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। मैंने प्रस्ताव देकर अपने वार्ड में खाली पड़ी जमीन पर बारातशाला का निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया था, किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद, राजस्व निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट लगाकर अपात्र लोगो को सब्सिडी दिलवाई है, इसकी जाँच कराई जाये। मेरे वार्ड में सफाई निरीक्षक नहीं आते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में समुचित कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। कृपया इस पर भी कार्यवाही कराई जाये।

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मेरे कम्पनी पुल के बगल से हीरापन्ना गेस्ट हाउस के सामने से जाने वाली सड़क तथा कैथरीन हॉस्पिटल की तरफ लखनऊ फाटक के पास का नाला अत्यधिक क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इस सड़क के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा कहा जाता था कि यह कैंटोन्मेण्ट बोर्ड का क्षेत्र है। मेरे द्वारा कैंटोन्मेण्ट बोर्ड से एन0ओ0सी0 लेकर मुख्य अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता को दे दी गई है। श्याम महोत्सव प्रारम्भ होने वाला है, छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तथा कैथरीन हास्पिटल भी है। कृपया इसको ध्यान में रख कर इस मार्ग को व नाले को शीघ्र बनवाया जाये। वार्ड में सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी 11-12 बजे चले जाते हैं। सफाई कर्मियों की ड्यूटी का समय कितने बजे से कितने बजे

जाये।

श्री इली सुहेल अहमद ने पूछा कि सेक्टरल इत्यादि कम्पनी को किस प्रकार विज्ञापन हेतु दिया गया, पूर्व अनुभव निरस्त किया

पर्यटन के दृष्टिगत हरियाली संस्था को तीन वर्षों के लिये विज्ञापन हेतु दिया गया।

श्री रघु सिंह, जौनल अधिकांश ने बताया कि 02 वर्षों से अधिक समय के लिये विज्ञापन अनुभव नहीं किया जा सका, परन्तु

कहने पर कार्य कराये, यह उचित नहीं है। उस धनराशि से सभी पार्कों के वार्ड क्षेत्र में कार्य कराये जाने चाहिये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि 40 दीनदयाल योजना के अन्तर्गत नगर निगम ब्याजमुक्त ऋण लेकर एक ही जनप्रतिनिधि के

जायगी।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि सभी पार्कों के क्षेत्र में कराये गये कार्यों की तालिका दिखावा ली जाये, स्थिति स्पष्ट हो

सभी पार्कों के क्षेत्र में भेदभाव के बिना समान रूप से कार्य कराये जाये।

श्री चौधरी बिल आयोग व अवस्थापना निधि की जो भी निरस्त आ रही है, उसमें एक ही विधान सभा में अधिक कार्य दिये जा रहे हैं।

कुल 13 पार्क लिये गये, जबकि सदन से प्रत्येक पार्क के क्षेत्र में ₹0 40.00 लाख की धनराशि से कार्य कराया जाना अनुमोदित किया गया

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों के वार्ड में एक-एक पार्क तथा एक पार्क माननीय समापति की अनुमति से

श्री राघवेंद्र मिश्रा ने कहा कि अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क विकसित कराये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक में

स्वयं अवधि पर्याप्त अपरान्त 03:00 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

.....

अपरान्त 02:00 बजे बैठक की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की गई।

में है, इसका भी निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाये।

तक है, अवगत कराया जाये। मेरे वार्ड क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध एवं प्राचीन काली मंदिर अखाड़ा है, जो वर्तमान में अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था

अध्यक्ष ने कहा कि अगले सदन में सभी पार्श्वों को उनके क्षेत्र में कराये गये कार्यों से अवगत कराया जायेगा। अभी हमारे पार्श्व ने बताया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में कार्य कराये जा रहे हैं। मेरे लिये सभी पार्श्व समान हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों में जब अधिक धनराशि से कार्य कराये जायेंगे तभी वहाँ पर कार्य नजर आयेंगे।

श्री सौरभ देव ने कहा कि मैंने एक प्रश्न पूँछा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पालिका स्टेडियम के लिये कार्यकारिणी के समक्ष आय-व्यय का जो ब्यौरा दिया गया था, उसे बजट में दर्शाया गया है या नहीं ? वहाँ पर तैनात रेगुलर व आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के वेतन पर कितना व्यय होता है तथा पालिका स्टेडियम की बुकिंग से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? इसके पूर्व में दक्षिण में स्थित नगर निगम के रतन लाल शर्मा स्टेडियम में क्रिकेट प्रशिक्षक हेतु निर्णय लिया गया, जिसके विरुद्ध वह विभागीय मिलीभगत से उच्च न्यायालय चले जाते हैं और न्यायालय से हमारे विरुद्ध निर्णय पारित करा लाते हैं, जिससे हमको अपमानित होना पड़ता है। इसकी भी जाँच कराकर सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि स्ट्रीट वेन्डर पर क्या कार्यवाही कराई जा रही है, अवगत कराया जाये ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि अस्पतालों से 100 मीटर की दूरी तक कोई वेंडिंग मार्केट नहीं होगी, क्या आप द्वारा उर्सला अस्पताल से एन0ओ0सी0 ली गई है ?

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि एस0वी0सी0 पर पुर्नविचार किया जाये साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उर्सला अस्पताल से एन0ओ0सी0 ली गई है या नहीं। प्रकरण की जाँच करा ली जाये तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि चूँकि यह प्रकरण हमारे वार्ड से सम्बन्धित है, इस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। हमारे एस0वी0सी0 सदस्य यहाँ मौजूद हैं, इसने पूँछ लिया जाये कि क्या यह एस0वी0सी0 की बैठक में उपस्थित थे। मैंने लॉटरी का विरोध किया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। रू0 एक-एक लाख की गुमटी बनाकर दी जा रही है, जिसमें दुकानदार द्वारा बताया जा रहा है कि हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो वह पैसा कहाँ जा रहा है ? रू0 80.00 लाख के टेण्डर कैसे हो गये, इससे वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है ?

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराते हुये नये सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाये।

महापौर/अध्यक्ष
(प्रसिद्धि पत्र)

हृ०.....

समाप्ति द्वारा सदन के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदेशों तक के लिये स्थिति की गई।

श्री मदन बाबू ने कहा कि मार्ग प्रकाश बिन्दु बन्द है, शिकायत करने पर मार्गप्रकाश प्रमाणी द्वारा न तो कोई सुनवाई की जाती है और न ही समानजनक ढंग से जवाब दिया जाता है।

श्री सुनील कर्नोजिया ने कहा कि अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे हैं इनके द्वारा मनमानी की जा रही है, पूर्व की भाँति अधिनियम में प्रविष्टानिब नियमों के तहत विधायी कार्यों की समीक्षा हेतु समितियों का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है ? यदि समितियों का गठन हो जायेगा तो अधिकारियों की निरक्षरता समाप्त हो जायेगी।

श्री राशिद महमूद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में जल निगम द्वारा समस्याओं का निराकरण करवाया जायेगा या नहीं ? मेरे वार्ड क्षेत्र में हलीम कॉलेज चौराह में लेकर चन्द्रिका देवी चौराह तक सीवर लाइन जाम है, जिसके कारण गंदा सीवर बह रहा है। इसका शीघ्र निराकरण कराया जाये।

श्री राशिद महमूद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में जल निगम द्वारा समस्याओं का निराकरण करवाया जायेगा या नहीं ? मेरे वार्ड क्षेत्र में प्रसृत कर सकता है। तदनुसार ही नियमों के तहत आवंटन किया गया है।

उल्लिखित किया गया है कि यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति 20 दिन के अन्दर मानवीय महापौर या अध्यक्ष के समक्ष के नगर पंच विषय समिति के गठन के विन्दु 4(1) में वर्णित नियमों के तहत टेण्डर बंदे गये हैं। नियमावली में यह भी स्पष्ट रूप से श्रीमती रीती गुप्ता ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पंच विर्केला (जीविका संरक्षण और पंच विषय विनियमन) नियमावली-2017

दिनांक— 28.12.2019 दिन शनिवार को स्थगित सदन की बैठक, जो दिनांक—08.01.2020 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त —

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/अध्यक्ष	20. श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य
2. श्री रमेश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	21. श्रीमती कविता सिंह	पार्षद/सदस्य
3. श्री शैलेश	पार्षद/सदस्य	22. श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
4. कु० लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	23. श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद/सदस्य
5. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद/सदस्य	24. श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद/सदस्य
6. श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	25. श्री शरद प्रकाश मिश्रा	पार्षद/सदस्य
7. श्रीमती आरती गौतम	पार्षद/सदस्य	26. श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद/सदस्य
8. श्री अवनीश खन्ना	पार्षद/सदस्य	27. श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
9. श्रीमती संगती बाली	पार्षद/सदस्य	28. श्री रमेश बाजपेई	पार्षद/सदस्य
10. श्री अजीत	पार्षद/सदस्य	29. श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद/सदस्य
11. श्री मदन बाबू	पार्षद/सदस्य	30. कु० विधि राजपाल	पार्षद/सदस्य
12. श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य	31. श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद/सदस्य
13. श्री सौरभ देव	पार्षद/सदस्य	32. श्री अशोक पाल	पार्षद/सदस्य
14. श्री राकेश कुमार	पार्षद/सदस्य	33. श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद/सदस्य
15. श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	34. श्री मनोज कुमार रातौर	पार्षद/सदस्य
16. श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद/सदस्य	35. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद/सदस्य
17. श्रीमती राधा देवी	पार्षद/सदस्य	36. श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद/सदस्य
18. श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद/सदस्य	37. कु० कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद/सदस्य
19. श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	38. श्रीमती नेहा यादव	पार्षद/सदस्य

पाठद/सदस्य	64. श्री जय प्रकाश पाल
पाठद/सदस्य	65. श्रीमती शाहिबा परवीन
पाठद/सदस्य	66. श्री राजीव सेलिया
पाठद/सदस्य	67. श्री मनोज कुमार पण्डेय
पाठद/सदस्य	68. श्री अमिल कुमार मेहरोत्रा
पाठद/सदस्य	69. श्रीमती संध्या
पाठद/सदस्य	70. श्री यशपाल सिंह
पाठद/सदस्य	71. श्री विकास जायसवाल
पाठद/सदस्य	72. श्री हरि शंकर गुला
पाठद/सदस्य	73. श्री सतीष साहू
पाठद/सदस्य	74. श्री राशिद आरफी
पाठद/सदस्य	75. श्रीमती अल्पना जायसवाल
पाठद/सदस्य	76. श्रीमती सुमन तिवेदी
पाठद/सदस्य	77. श्रीमती मेनका सिंह संगर
पाठद/सदस्य	78. श्री अनूप कुमार शंकरा
पाठद/सदस्य	79. श्री गुरु नारायण गुला
पाठद/सदस्य	80. श्री राघवेंद्र मिश्रा
पाठद/सदस्य	81. श्री प्रमोद जायसवाल
पाठद/सदस्य	82. श्री नवीन पण्डित
पाठद/सदस्य	83. श्री आशीद त्रिपाठी
पाठद/सदस्य	84. श्री प्रशान्त शंकरा
पाठद/सदस्य	85. श्रीमती लीना खर्जन
पाठद/सदस्य	86. श्री मी0 अमीन
पाठद/सदस्य	87. श्री दीपक शर्मा
पाठद/सदस्य	88. श्री कौसर अली

पाठद/सदस्य	39. श्री विजय कुमार
पाठद/सदस्य	40. श्री अर्पित यादव
पाठद/सदस्य	41. श्री दिनेश त्रिपाठी
पाठद/सदस्य	42. श्रीमती प्रभा सिंह चौहान
पाठद/सदस्य	43. श्री अश्वनी चड्ढा
पाठद/सदस्य	44. श्री महेंद्र नाथ शंकरा
पाठद/सदस्य	45. श्री सुशील अवस्था 'गुड्डू'
पाठद/सदस्य	46. श्रीमती नीरू मिश्रा
पाठद/सदस्य	47. श्री सुमित कुमार पाल
पाठद/सदस्य	48. श्री विजय यादव
पाठद/सदस्य	49. श्री अमिल वर्मा
पाठद/सदस्य	50. श्री नूर आत्म
पाठद/सदस्य	51. श्री कौशला चन्द पण्डेय
पाठद/सदस्य	52. श्री मी0 अमिर खान
पाठद/सदस्य	53. श्री लिवेंद्र
पाठद/सदस्य	54. श्री कमल शंकरा बेबी
पाठद/सदस्य	55. श्री सीरम त्रिपाठी
पाठद/सदस्य	56. श्री रूपा प्रसाद
पाठद/सदस्य	57. श्री नीरज राजपूडे
पाठद/सदस्य	58. श्रीमती यशोदा देवी
पाठद/सदस्य	59. श्रीमती दीपा
पाठद/सदस्य	60. श्रीमती शकुन्तला देवी
पाठद/सदस्य	61. श्री अरविन्द यादव
पाठद/सदस्य	62. श्रीमती चन्द्रावती
पाठद/सदस्य	63. श्री विद्याकल अली

89. श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
90. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
91. श्री मन्तू रहमान	पार्षद / सदस्य
92. श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य
93. श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
94. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
95. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य
पदेन सदस्य	
96. श्री दिलीप सिंह यादव	सदस्य विधान परिषद

अधिकारीगण

1. श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4. श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
5. श्री रमेश कुमार निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. श्री कैलाश सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
7. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'

वन्देमातरम् गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने कहा कि आज का सदन सिर्फ विकास कार्य पर चर्चा के लिये होगा साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सभी पार्षदों के यहाँ कितना कार्य कराया गया है, स्थिति स्पष्ट करते हुये तदनुसार जिस पार्षद के यहाँ विकास कार्य कम हुये हैं, उसके यहाँ और कार्य कराये जायेंगे। पार्षद आज अपनी बात कहेंगे भी और दूसरे की सुनेंगे भी। अतः सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुये महानगर के विकास पर सार्थक चर्चा की जाये, मैं भी पूर्व में निर्वाचित सदन की 10 वर्ष पार्षद रही हूँ। इसी के साथ नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

तदनुक्रम में नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को बैठक की कार्यवाही संचालित करने के निर्देश दिये।

प्रस्ताव संख्या 62

दिनांक 05.12.2018 को सम्पन्न हुई मा0 सदन की बैठक का प्रस्ताव संख्या-47 जो अगली सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

निवेदन है कि हम सभी आनरेरी चिकित्सक होम्योपैथिक, विगत लम्बे अर्से से नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सीय सेवाएँ दे रहे हैं। हमें गत कुछ वर्षों से आनरेरियम मान रूपया दस हजार (10000/-) प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो वर्तमान में अपर्याप्त

होम्योपैथिक आनरेरी चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

करने के लिये मा10 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृताएँ हेतु प्रस्तुत है :-

दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई मा10 कार्यकारिणी समिति की बैठक का दृष्टल प्रस्ताव संख्या-167 जो अगली सदन की बैठक में प्रस्तुत

प्रस्ताव संख्या-63

.....
 ध्वनिमत से निरस्त किया गया।

न पड़े।

किया जाये कि उक्त ऋण की अदायगी, कम वार्षिक प्रिमियम के साथ अधिक वर्षों में की जाय ताकि काटी गयी धनराशि का अधिक प्रभाव वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम को प्राप्त होने वाली धनराशि से की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन को यह भी अनुरोध पत्र प्रेषित तलकम में अवगत करना है कि रिवाँडिंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में निकाय अंशों की धनराशि की कटौती राज्य

प्रेषित है।

कार्यों में से 10.00 करोड़ के कार्यों का वित्त पोषण उक्त योजना से किये जाने हेतु प्रस्ताव मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृताएँ योजनान्तर्गत धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में तात्कालिक आवष्यकता के दृष्टिगत उनकी माँग पर उपलब्ध कराये हेतु पत्र में वर्णित श्री देवेन्द्र सिंह मोले ने विभिन्न 64 सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास सचिव, नगर विकास अर्जुमाग-9, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.09.2018 द्वारा मा10 सांसद, लोकसभा, अकबरपुर कानपुर क्षेत्र सादर अवगत करना है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.06.2018 के क्रम में विषय

हैं। चिकित्सालयों में दवायें न उपलब्ध होने से उसे सुचारु रूप से चलाने में समस्या होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 20000/- रुपये करने का कष्ट करें।

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने कहा कि यह चिकित्सक आउटसोर्सिंग पर है या संविदा पर ?

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने अवगत कराया कि यह चिकित्सक ऑनरेरियम पर कार्यरत है।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो रू० 5000-5000 हजार के लिये दिनभर कार्य किया करते हैं, ऐसे में इनका ऑनरेरियम रू० 10000/- से बढ़ाकर रू० 20000/- किया जाना, उचित प्रतीत नहीं होता है। ऑनरेरियम पर कार्यरत चिकित्सक के ऑनरेरियम में जो वृद्धि का प्रस्ताव है, वह सिर्फ चिकित्सकों के लिये क्यों ? नगर निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वितन बढ़ोत्तरी हेतु कोई प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ? आउटसोर्सिंग कर्मियों को वेतन रू० 9000/- स्वीकृत है, किन्तु रू० 7500/- भुगतान किया जाता है, जबकि ई०एस०आई० लगभग रू० 300-400 कटता है, शेष रू० 1000/- कहाँ जाता है ?

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि रू० 20000/- चिकित्सकों का ऑनरेरियम बढ़ाये जाने पर चर्चा की जा रही है, जबकि ऑउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। क्या आप यहा अवगत करायेंगे कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? नगर निगम में सबसे अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं, जो नगर निगम का लगभग 70 प्रतिशत कार्य करते हैं। स्थायी कर्मचारियों के लिये प्रत्येक 10 वर्ष में वेतनमान तथा समय-समय पर मेंहगाई भत्ते, वार्षिक वेतनवृद्धि का प्राविधान है। इसी प्रकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी काम के बराबर दाम दिया जाये। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। भारत सरकार द्वारा अनस्किल्ड/सेमीस्किल्ड/हाईस्किल्ड तीन श्रेणीय में कर्मचारियों को विभक्त करते हुये वेतन निर्धारण किया जाता है तथा कर्मचारियों को ई०पी०एफ० आदि की कटौती का चालान दिखाने के उपरान्त ही टेकेदार को भुगतान किया जाता है। यह भी अवगत करायें कि नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कैसे किया जाता है ? और कितना भुगतान किया जाता है ? नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में भय व्याप्त है तथा क्योंकि उनका वेतन भी समय से नहीं मिलता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ई०एस०आई० फण्ड का लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री निरीश चन्दा ने कहा कि पाकों में हम सब प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं, परन्तु आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मातियों का वेतन बहुत कम है। मातियों को रु० 194/- प्रतिदिन दिया जा रहा है, जबकि भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को रु० 350/- प्रतिदिन मिलता है, जो मातियों के सामाजिक स्तर के प्रतिकूल है। नगर निगम के पाकों में संख्या के सापेक्ष अव्यक्त संख्या में माती नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह, सहायक नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की विभिन्न सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक इत्यादि मिलाकर लगभग 2500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। सभी को कैंटेनरी के हिसाब से अलग-अलग वेतन दिया जाता है। सेवा प्रदान करने वाली कम्पनी द्वारा 2000 रु० फण्ड कटौती का चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है।

श्री राघवेंद्र मिश्रा ने कहा कि नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बहुत सी आतियाँ हैं। चूँकि यह भी हमारे बीच के भाई हैं, इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा एवं उपचार की आवश्यकता है। अतः इसको ध्यान में रखते हुये इनके वेतन निर्धारण पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि भ्रम विमग न्यूनतम वेतन भुगतान हेतु श्रेणीवार अलग-अलग निर्देश देता है। यदि मा० कार्यकारिणी समिति या सदन से कोई प्रस्ताव आता है, तो उसके अर्जुन वेतन बढ़ाये जाने हेतु विचार किया जाता है। इसी प्रकार एक शिक्षक की भी 2000 रु० न जमा होने की शिकायत आयी थी, जिस पर दिखवाने के उपरान्त पता चला था कि उनका 2000 रु० जमा हुआ है या करने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। अतः किसी एक कर्मी का स्टेटमेंट दिखवा लिया जाये कि उसका 2000 रु० जमा हुआ है या नहीं। यदि इसके उपरान्त भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उनका स्टेटमेंट उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पाकों की संख्या के अनुसार मातियों की संख्या बढ़ाई जाये तथा उन्हें भी अन्य आउटसोर्सिंग कर्मियों की भाँति वेतन दिया जाये।

..... होन्योपैहिक आनररी चिकित्सकों का आनरियम रु० 12000/- (द्वयोषा बारह हजार मात्र) किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि मैंने पिछले सदन में प्रश्न उठाये थे, उसका जवाब आज तक नहीं दिया गया है, मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप गड़ढामुक्त शहर क्यों नहीं हुआ ? मा0 प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में बनवाये गये शौचालय, आज तक अपूर्ण हैं, वह कब पूर्ण कराये जायेंगे ?

अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता को श्री प्रमोद जायसवाल की शिकायत सड़क पैच एवं शौचालयों के निर्माण की जाँच मा0 पार्षदों एवं अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर कार्यवाही की जायें।

श्री राशिद आरफी ने कहा कि कानपुर महानगर के विभिन्न स्थानों पर केस्कों द्वारा रोड कटिंग कराई जा रही है, परन्तु नगर निगम द्वारा लगभग 15 वर्ष रोड कटिंग की दर से धनराशि जमा कराई जा रही है। फुटपाथों में अतिक्रमण कर ट्रान्सफार्मर लगाये जा रहे हैं, परन्तु हमारी स्ट्रीट लाईटों को लाईनों में नहीं जोड़ा जा रहा है। भूमिगत डाली जा रही बिजली की लाईनों के केबिल बॉक्सों को भी गलियों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लगाया जा रहा है। नगर निगम इस पर कार्यवाही करते हुये केस्कों से ट्रॉन्सफार्मर व केबिल बॉक्सों का यूजर चार्ज सर्किल रेट के आधार पर वसूलना सुनिश्चित करें। हमारे वार्ड में कूड़ा उठान व सफाई की स्थिति बहुत खराब है, वार्ड में कोई कूड़ा घर न होने के कारण कूड़ा सड़क पर फैला रहता है, इस पर ध्यान दिया जाये। मेरे वार्ड के अन्तर्गत नगर निगम की दलेलपुरवा बारातशाला है, जो 01 जनवरी, 2019 से वर्तमान पार्षद की देखरेख में चल रहा है, जिसका किराया लगभग रूपया एक लाख से अधिक प्राप्त हुआ है, जो पार्षद के पास सुरक्षित है। यदि नगर निगम द्वारा इस बारातशाला को मैरिजहॉल के रूप में बनवा दिया जाये तो इससे नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग ₹0 60.00 लाख की आय होगी, इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी और उस धनराशि से शहर में विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि मेरे वार्ड में केस्कों के निर्देशन पर प्राइवेट कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत भूमिगत केबिल डाली जा चुकी है। इन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नगर निगम से स्थल की रोड कटिंग हेतु ली गई अनापत्ति/एन0ओ0सी0 के सापेक्ष ज्यादा स्थल पर रोड कटिंग कराई जाती है, जिससे क्षेत्रीय नागरिक परेशान होते हैं, जबकि नगर निगम को पूरी सड़क बनानी पड़ती है। तीन क्षेत्रों में रोड कटिंग की अनापत्ति नगर निगम द्वारा दी गई, जिसमें केस्कों द्वारा रोड कटिंग मद में ₹0 37.00 लाख जमा किया गया था, जबकि सिर्फ मेरे वार्ड में ही लगभग ₹0 32.00 लाख के कार्य शेष हैं। मुझे यह अवगत कराया जाये कि यह धनराशि कहाँ गई ? यहाँ मौजूद अधिकारियों से पूँछा जाये कि किसी पार्षद के वार्ड क्षेत्र की रोड कटिंग का पैसा कहाँ लगाया गया है, क्योंकि अधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाने के बाद हम फिर वहीं आकर खड़े जो जाते हैं। वार्ड में सर्वप्रथम जवाबदेही पार्षद की होती है, सांसद/विधायक की नहीं। क्षेत्रीय जनता सुबह-सुबह शिकायतें लेकर पार्षदों को घेरती है।

श्री राजीव सिंह ने कहा कि सी०ई०जी०एल० कम्पनी द्वारा 80.00 लाख की धनराशि रोड कटिंग मद में नगर निगम में जमा की गई, किन्तु तदनुसार सड़क पुर्ननिर्माण कार्य नहीं हुआ, जबकि मा० कार्यकारिणी समिति/सदन की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिस गार्ड की रोड कटिंग होगी, उसकी धनराशि उसी गार्ड में लगाई जायेगी। किन्तु अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। नगर निगम में पैववर्क के नाम पर मैटेरियल खरीदा जाता है, किन्तु पैववर्क कहाँ किया जाता है, इसकी जानकारी क्षीय पावर्ड को नहीं दी जाती है। जिससे नगर निगम में आर्थिक नुकसान हो रहा है। विगत दो वर्षों में कार्य की गुणवत्ता खराब होने पर किसी भी कम्पनी की बैंक गारण्टी जमा नहीं की गई है।

श्री राजीव सिंहल अहमद ने कहा कि केंद्रों द्वारा रोड कटिंग का कार्य प्राइवेट कम्पनी को देकर आर्डी० एवं एल० एल० के माध्यम से कराया जा रहा है। कम्पनियों द्वारा रोड कटिंग की धनराशि पूरी नहीं जमा की जा रही है। क्षेत्र में रोड कटिंग कुछ होती है और पैसा कुछ जमा किया जाता है। पूर्व में उ०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत दो रेलवे लाइनें में क्रॉस दिया गया था, जिसका रेलवे द्वारा एक क्रॉस का रु० 17.00 लाख तथा दूसरे क्रॉस का रु० 14.00 लाख लिया गया था। इसी प्रकार हम केंद्रों से भी यूजर जार्ब ले, क्योंकि केंद्रों द्वारा भी रोड पर ट्रॉन्सफार्मर व कैंबिल बोक्स लगाये जा रहे हैं। केंद्रों से ट्रॉन्सफार्मरवाइज यूल्क जमा कराया जाना चाहिये। 04 गार्डों का रु० 37.00 लाख केंद्रों द्वारा जमा कराया गया, जिसमें रोड कटिंग का पैसा पुरानी दर से लिया जा रहा है। रोड कटिंग से सड़कें व गलीपिट बख्त हो जाती है, अतः फ्रैकन्टी जार्ब के नाम पर एक साथ धन जमा कराया जाये। इनके द्वारा स्थल के पिट के हिसाब से पैसे जमा किये जाते हैं, जबकि हमकी पूरी सड़क का निर्माण कराना पड़ता है। केंद्रों की आय दिन बिजली दरें बढ़ती जा रही है। अतः नगर निगम को भी इस पर ध्यान देकर केंद्रों से बर्खाशी करे।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि पूरे महानगर में मनमाने ढंग से रोड कटिंग की जा रही है, जिससे सीवर/पानी की लाइनें एवं गलीपिट टूट रही हैं, जनता परेशान होती है। मा० अख्यत महोदय आपने प्रत्येक गार्ड में गलीपिट के लिये रु० 01.00 लाख की धनराशि चौदहवें बिल आयोजन के अन्तर्गत दी है, परन्तु कोई भी आवर अभियन्ता गलीपिट का कार्य करने को तैयार नहीं है। भरे गार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 15 स्थानों पर पाइप लाइन टूट गई है, लगभग एक माह व्यतीत होने के बाद भी कार्य नहीं हुआ है। खरब आरव विधान के अन्तर्गत दीवारों की प्लिन्थ का कार्य कराया जाता है, जो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। अतः दीवारों पर प्लिन्थ के स्थान पर सेन्सरी के टक्कन व गलीपिट का निर्माण कराया जाये, जो क्षीय जनता को इसका लाभ मिलेगा।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अभी सदस्यों ने सदन के सामने जो बात रखी उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि रोड कटिंग के मद में जमा धनराशि का विवरण अभियन्ता विभाग से क्षेत्रवार माँगा गया है। संज्ञान में आया है कि रोड कटिंग की धनराशि गार्डवाइज न जमा होकर सामूहिक जमा हो गई थी, जिस कारण यह स्थिति बनी। यदि किसी गार्ड में रोड कटिंग की गई है और उसकी धनराशि नगर निगम में जमा है परन्तु प्रस्ताव क्षेत्र में निर्माण कार्य किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है तो उसका निर्माण नगर निगम निधि से करा दिया जायेगा।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि महाप्रबन्धक 'जलकल' को मैंने पत्र लिखा था कि वार्ड-45 के ट्यूबवेल की मोटर 15 बार खराब हो चुकी है तथा ट्यूबवेल लगभग समाप्त हो गया है, यदि इसको समय से रिबोर करा दिया जाये तो क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो जायेगी, क्योंकि इस ट्यूबवेल में पूर्व में ही 06-07 पाइप बढ़ाये जा चुके हैं इसलिये अब पाईप बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। इस ट्यूबवेल के खराब हो जाने के कारण आस-पास क्षेत्र की लगभग 50000 जनता पानी के बिना प्रभावित है। जल निगम से जलापूर्ति हेतु कहने पर बताया जाता है, कि शहर का किनारा होने के कारण पानी नहीं पहुँच सकता है। अतः इस पर ध्यान दिया जाये। मेरे वार्ड में दो सम्पवेल भी है, उनकी भी मोटरें खराब थी, जब मैंने जलकल के कार्यालय में ताला डाला, तब जाकर मोटरें ठीक हुई। जलकल विभाग ने अपनी कार्य प्रणाली की क्या स्थिति बना रखी है, इससे स्वतः स्पष्ट होता है। कृपया महाप्रबन्धक 'जलकल' इस सम्बन्ध में अवगत करायें।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने अवगत कराया कि उक्त ट्यूबवेल की कई बार रिपेयरिंग भी हो चुकी है, परन्तु बार-बार खराब हो जाता है, पिछले वित्तीय वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग में प्रश्नगत ट्यूबवेल रिबोर स्वीकृत नहीं हुआ था, जो 15वें वित्त आयोग से कराये जाने वाले कार्य में सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे नई मोटर क्रय कराकर डाल दी जायेगी।

अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक 'जलकल' को शीघ्र रिबोर कराये जाने हेतु 14 वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मेरे वार्ड स्थित शिव मन्दिर का शिवलिंग सीवर भराव के कारण डूब गया है, मैं सावन के महीने से महाप्रबन्धक जलकल को सीवर सफाई कराने हेतु कह रहा हूँ, किन्तु सफाई नहीं कराई जा रही। इससे स्पष्ट होता है कि महाप्रबन्धक जी कानपुर नगर का सांप्रदायिक महौल बिगाड़ना चाहते हैं। चूँकि जलकल विभाग के कार्यों में अत्यधिक अनियमिततायें हैं अतः इनके कार्यों की जाँच कराई जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जब रा0पा0 पार्षद दल के नेता के कार्यों की यह स्थिति है, तो आम आदमी की शिकायतों का क्या होता होगा।

श्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि इसीप्रकार मेरे वार्ड क्षेत्र स्थित मकबरे की सीवर सफाई जलकल विभाग द्वारा नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। वहाँ की सफाई सुपर सकर मशीन से कराई जाये।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने अवगत कराया कि प्रश्नगत स्थल पर जेटिंग मशीन से सफाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पर सुपर सकर मशीन से सीवर सफाई कराई जायेगी।

श्री सतीश वर्मा, परियोजना अधिकारी, डूँडा ने अवगत कराया कि डूँडा का कोई बजट नहीं होता है। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेजे जाते हैं, उनमें से जो प्रस्ताव शासन से स्वीकृत होकर आते हैं, उन्हीं पर कार्य कराया जाता है। पूर्व में ₹ 15.00 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें ₹ 07.00 करोड़ की धनराशि के कार्य स्वीकृत हुये हैं, इसमें श्री महेंद्र पाण्डेय, पार्षद का भी प्रस्ताव समाहित है।

क्या कार्य कराया गया, अवगत कराया जाये ?

इन्क के द्वारा आज तक किसी भी वाड की मलिन बस्ती में कोई कार्य नहीं कराया गया है। इस 110 पार्षद है, किस पार्षद के प्रस्ताव पर डूँडा द्वारा

बस्ती में डूँडा द्वारा कार्य कराया जायेगा। किन्तु आज तक डूँडा द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है, जबकि डूँडा में करौंडी-का बजट आता है, किन्तु श्री महेंद्र पाण्डेय 'गर्पू' ने कहा कि जब हम निर्वाचित होकर आये थे, तो अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि प्रत्येक वाड में एक-एक मलिन

अनुसार वाडों में शीघ्रापर बनवाया जाये।

जो कि आठ वाडों की एक मुख्य सड़क है, वह भी अत्याधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इसका भी शीघ्र निर्माण कराया जाये। पूर्व में लिये गये निर्णय के उचित सड़क का निर्माण कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक नहीं कराया गया है, इसी के साथ थानेदार मन्दिर से पत्तकी कल्याणपुर रोड अत्याधिक क्षतिग्रस्त है, इस मार्ग से रामनवमी शोभायात्रा निकलती है। यात्रा में लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, इसे शीघ्र बनवाया जाये।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि मैंने पूर्व की बैठक में अवगत कराया था कि मेरे वाड क्षेत्र के अन्तर्गत रवेल पैलेस से धनुकाना तक सड़क

संस्था को कालीसूची में डालते हुये अन्य संस्था के माध्यम से शौचालय बनवाने एवज ल निकाली हेतु मोटर संचालित करने को भी कहा।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को एकल शौचालय बनवाने हेतु सम्बन्धित संस्था को आदेशित करने के निर्देश दिये साथ ही अन्यथा की स्थिति में

बीमारियाँ फैल रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाये।

पाइप डालकर गांदा पानी निकालने के लिये मोटर लगाई गई, उन मोटरों के बन्द होने के कारण गांदा पानी बैंक होकर क्षेत्र में भर रहा है, जिससे तक शौचालय नहीं बनाये गये हैं। गंगा बैराज पर प्रवेश व निकल हुए बनवाया जाये। गंगा में गिरने वाले नालों के गांदा पानी को सोकने के लिये लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अटल घाट आये थे, तब वहाँ पर शौचालय हेतु 20-25 गड्डे एक संस्था द्वारा बनाये गये थे, परन्तु आज शून्क रिया जा रहा है तथा आगुत्की से बदसलूकी की जाती है, जबकि नगर निगम द्वारा मन्दिर अथवा धार्मिक स्थानों पर कोई पाकिंग शून्क नहीं

श्री मदन गाँवू ने कहा कि हमारे वाड में अटल घाट है। वहाँ पर नगर निगम द्वारा आवंटित गार्डन स्टेपड में संचालक द्वारा मनमाना पाकिंग

अध्यक्ष ने प्रश्नगत स्थलों की सफाई सुपर सकर मशीन से कराने हेतु महाप्रबन्धक 'जलकल' को निर्देशित किया।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि कानपुर महानगर की 06 मलिन बस्तियों में से 04 मलिन बस्तियों की निविदायें आमंत्रित हो चुकी हैं। सभी मलिन बस्तियों में कार्य कराया जायेगा।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि मेरा वार्ड सबसे अविकसित वार्ड है। आज बारिश में सड़कें कीचड़ से भर गई हैं। सड़क निर्माण की पत्रावली बनवाने में 06-07 माह लग जाते हैं, किन्तु ठेकेदारों को कई स्थानों पर कार्य आवंटित होने के कारण उनके द्वारा कार्य को समय से पूर्ण नहीं किया जाता है, इसको दिखवाया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि सदन की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आये श्री दिलीप सिंह यादव, जो पदेन सदस्य है, का मैं स्वागत करती हूँ।

श्री सौरभ तिवारी ने कहा कि मेरा वार्ड स्वर्ण जयंती विहार है, जहाँ पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने स्वर्ण जयंती विहार योजना के हस्तान्तरण के समय नगर निगम को एक अरब तीन करोड़ पंद्रह लाख तैंतिस हजार रुपया क्षेत्र के विकास कार्य हेतु दिया था, किन्तु आज तक नगर निगम द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराये गये हैं, इसकी जाँच कराई जाये। यह प्रकरण मैं कई बार पूर्व में सदन की बैठक में उठा चुका हूँ। अध्यक्ष महोदय मेरे वार्ड को अतिक्रमणकर्ताओं ने कबाड़ बना दिया है। खुले में प्लास्टिक जलाई जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 103 अवैध होर्डिंग्स लगी है। इन अराजक तत्वों से आर्थिक दण्ड वसूला जाये।

अध्यक्ष ने जोनल अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रश्नगत स्थल को दिखवा कर कबाड़ का कार्य कर रहे व्यापारियों से यूजर चार्ज वसूला जाये तथा यूजर चार्ज जमा न किये जाने पर सामान जब्त कर लिया जाये। कानपुर को इन्दौर की तर्ज पर होर्डिंगमुक्त बनाना है।

श्री सुनील कनौजिया कहा कि मेरे वार्ड स्थित ओ-ब्लाक किदवई नगर सब्जीमण्डी कानपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तान्तरित होनी है, यहाँ नाले, नालियाँ सिल्ट से भरी हैं, क्षेत्र में गन्दा पानी भरा है, सड़ांध फैल रही है, अतः कानपुर विकास प्राधिकरण से क्षेत्र के हस्तान्तरण की शीघ्र कार्यवाही कराई जाये। इसी के साथ यह भी अवगत कराना है कि वार्ड-14 में ही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जूही थाने के पीछे 26 भूखण्ड विकसित कर नगर निगम को योजना हस्तान्तरित तो कर दी गई है, किन्तु आज तक वहाँ नगर निगम द्वारा कोई सफाई कर्मी तैनात नहीं किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त है, बीमारियाँ फैल रही हैं। अतः जूही थाने के पीछे की योजना में सफाई कर्मी तैनात करने की कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि जूही थाने के पीछे स्थित भवन स्वामियों का प्रतिनिधि मण्डल भी सफाई कर्मी की तैनाती हेतु मुझसे मिल चुका है। अतः नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत स्थल पर एक सफाई कर्मी तैनात करना सुनिश्चित करें।

श्री दिलीप सिंह यादव ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि सदन पीठ पर, जो माननीय महाधाय जी बैठी है, वही अध्यक्ष है, उनका सम्मान सर्वोपरि है। आज आप पार्षद हैं, कल विधायक व सांसद होंगे, ऐसी भरी सुनकामना है। अध्यक्ष पीठ का सम्मान सर्वोच्च है, भैया सभी से अनुरोध है कि वह अपनी समस्यार्यों को पीठ के समक्ष मर्यादापूर्वक प्रस्तुत करें, उसका समाधान अवश्य होगा, मुझे विश्वास है। अध्यक्ष महोदय करने के लिये कहा।

इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिये। इसका विशेष ध्यान रखा जाये। इसी के साथ सदन अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह यादव से अपने विचार व्यक्त सामानित पार्षद है, आप इनका कार्य करें या न करें किन्तु इनका सम्मान तो करना ही होगा। कार्य की गुणवत्ता व मानक पर ध्यान देना होगा, अध्यक्ष ने जोनल अभियन्ता जोन-4 से कहा कि यदि आपके प्रति हमारे पार्षद इस प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नहीं है। यह हमारे की बात पार्षद जी कर रही है, उसमें एक पक्षर को लेकर आक्रोष था।

श्री पुनीत ओझा, जोनल अभियन्ता जोन-4 ने अवगत कराया कि अधिकांश का कोई ठेकेदार नहीं होता है। अवस्थापना निधि के लिये कार्य

हूँ श्री पुनीत ओझा, जोनल अभियन्ता जोन-4 का पार्षदों से बात करने का तरीका सही नहीं है।

व्यवहार ठीक नहीं दिखता। वह न तो फोन उठाते हैं और न ही ठीक ढंग से बात करते हैं। इस पर श्रीमती नर्मिता मिश्रा ने भी सहमति व्यक्त करते जाँच कराई जाये। अध्यक्ष महोदय यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित जोनल अभियन्ता से जब भी मैंने शिकायत की है, तो उनका भेरे प्रति सम्बन्ध में मैंने पूर्व में कई बार शिकायत की थी, उसकी अनदेखी कर कार्य एक ही बार में कराकर कार्य का भुगतान भी करा दिया गया है, इसकी जाँच होना था, वहाँ नहीं हुआ। नाल में रस्तेब के ऊपर रस्तेब डाल दी गई है, सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया, इस रूझी लक्ष्मी कोशी ने कहा कि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत सीखामऊ नाल के निर्माण में रुपया 53.00 लाख का कार्य होना था किन्तु कार्य

भेरे वार्ड में आर0310 प्लान्ट लगाया जाये।

अन्तर्गत नौरैयारूड्डा में क्रमियमसुरत पानी आना है, जलकल विभाग में शिकायत करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। समस्या का समाधान कराने हेतु

श्री जयप्रकाश पाल ने कहा कि पनकी गाँवसिंह स्थित नगर निगम कूड़ा प्लान्ट भेरे वार्ड के निकट स्थित है, जिसके कारण वार्ड क्षेत्र के

रही है, जिसके द्वारा भी अलाव हेतु गीली लकड़ी आपूर्ति की गई है, उसकी जाँच कराई जानी चाहिये।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि इस समय भीष्ण सर्दी चल रही है। ऐसे में नगर निगम द्वारा अलाव हेतु गीली लकड़ी स्थलों पर भेजी जा

श्रीमती अल्पना जायसवाल ने कहा कि किस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी रैनाल किये गये हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये ?

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि पूरे शहर में अमृत योजना एवं नमामि गंगे के अन्तर्गत कई कार्य चल रहे हैं, उसके लिये धन्यवाद। प्रायः देखा जा रहा है कि कार्य जिस ठेकेदार को आवंटित होता है, उसे वह पेटी ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराता है, जिससे सड़कों की अनियमित खुदाई की जाती है तथा सही ढंग से उन्हें मोटरेबुल नहीं किया जाता है, परिणाम स्वरूप जनता परेशान होती है। कोई जॉली कम्पनी है, जिसके द्वारा सड़क की खुदाई तो कर दी गई, परन्तु मरम्मत नहीं कराई गई, उसके सम्बन्ध में मैंने कई पत्र भी लिखे हैं। अतः सुझाव है कि जिन कम्पनियों द्वारा कार्य किये जा रहे हैं, उनसे ही उस सड़क की समय से मरम्मत भी कराई जाये। अन्त में आप सभी पार्षदों से अनुरोध है कि शहर के विकास एवं समाज के कल्याण के लिये सदन में सार्थक चर्चा करे, तो उसका निष्कर्ष भी निकलेगा।

सभापति ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसी सदन के सदस्य सांसद/विधायक हुये हैं। मैं भी दस वर्ष पार्षद रही हूँ और वर्तमान में महापौर हूँ। हमारे कुछ सदस्यों को लगता है कि मैं उनके साथ भेद-भाव कर रही हूँ, किन्तु ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिये सभी पार्षद समान हैं। अतः सभी पार्षद शान्ति एवं मर्यादित ढंग से अपनी बात कहे साथ ही अधिकारियों को भी सुने। तभी शहर का समग्र विकास हो सकेगा।

श्री महेन्द्र शुक्ला ने कहा कि हमने नगर आयुक्त जी को एक पत्र दिया है, कि जलकल में यदि 04 सुपर सकर मशीन किसी योजना के तहत खरीद ली जाये, तो शहर की सीवर समस्या का निराकरण हो जायेगा। हमारे वार्ड में 30 फुट गहरा नाला है, जिसकी सफाई नहीं हो पा रही है, लेनिन पार्क के पास हजारों लीटर पानी लीकेज के कारण बह रहा है, लेकिन जल निगम का कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिये नहीं आया है। चट्टे, जो सीवर भराव का कारण है, अभी तक पूर्ण रूप से शहर से बाहर नहीं किये गये, प्रभावी अभियान चलाया जाये। प्रेम नगर स्कूल के पास पानी की टंकी से पूरे क्षेत्र में सफाई नहीं हो पा रही है, इसे भी दिखवाया जाये।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप द्वारा शहर से चट्टे हटवाये जा रहे हैं, यह स्वागत योग्य कदम है, इसमें पर्याप्त पुलिस बल प्राप्त करते हुये पार्षदों के सहयोग से शहर के चट्टे हटवाये जाये, हम सभी आपके साथ हैं।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि जलकल विभाग को किसी योजना की धनराशि स्वीकृत किये जाने से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जलकल विभाग को पैसा दिया जाना पैसे की बर्बादी है। जलकल विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जाँच कराई जाये।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि चट्टा वालों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन पूर्व में दी गई है, उसकी जाँच कराते हुये चट्टों को शहर से बाहर कराने की कार्यवाही की जाये।

श्री आशोक गुप्ता ने कहा कि सभी पार्षदों के कार्य के लिये सचिव कार्यालय है, किन्तु पार्षदों के पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, जबकि सचिव कार्यालय में 28 कर्मचारियों का स्टाफ है, किन्तु कार्यालय में 04-05 लोग ही मिलते हैं, इसको दिखवाया जाये। अथवा महोदय भी सदन में सभी पार्षदों की तरफ से कहना चाहता है कि लिये गये पत्रों का समय से जवाब दिलाया जाये। आदेशों/निर्णयों का अनुपालन नहीं होता है, साथ से जवाब पत्र लौटाते हैं। नगर निगम के जनसूचना विभाग में भी शिकायतें मिलते एक-दो वर्ष से लम्बित हैं, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, जिसके प्रभारी अपर नगर आयुक्त प्रथम है। यदि उन्हीं पिछले दो-तीन माह में जनसूचना के प्रकरणों हेतु कोई तारीख लगाई गई हो, तो अवगत कराने का कष्ट करें। गृहकार के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनमें पार्षदों के पत्रों के बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है। गृहकार सुधार के प्रार्थना पत्र एक-एक वर्ष पूरे रहते हैं। वर्ष 2008 में लागू की गई सारलकर योजना का अभी तक नहीं हुआ है और वर्ष 2016 में पुनः कर बढ़ा दिया गया है। कृपया नगर आयुक्त मार्गदर्शन करें कि हम सभी पार्षद क्या करें।

शुद्ध शहर सर्टिफिकेट किया जायेगा।
 देना है, जिससे सीवर निकाली जायित होती है, परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में गन्दे पानी का भयव होता है, बीमारियाँ फैलती हैं। अतः प्रतिबद्धता दिखाते बतया था, जबकि चट्टों के कारण ही सीवर लाइनें बाँक होती हैं। चट्टों का गोबर व मूसा मिलकर सीवर लाइनों को सीमेंट की भाँति जाम कर अग्रक्ष ने कहा कि सावन के महीने में कानपुर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, सभी सांसदों/विधायकों ने नगर निगम को दोषी ठहराया था, जबकि चट्टों के कारण ही सीवर लाइनें बाँक होती हैं। चट्टों का गोबर व मूसा मिलकर सीवर लाइनों को सीमेंट की भाँति जाम कर निकाल कराने का प्रस्ताव कई बार दिया गया, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नगर निगम द्वारा नहीं की गई।

श्री कमल श्रुतल "बेबी" ने कहा कि अग्रक्ष जी आपको हमारे बाई से अधिक प्रेम है, जिससे आप एक-दो दिन में भरे बाई के चट्टे हटाने लगी है, कहने का मतलब है कि हम पार्षद भाईयों को आपके कार्यालय में कुछ नया मिलना चाहिये। भरे बाई में जो चट्टा खुला है, मैं भी उसके विरोध में हूँ। बाई के अन्तर्गत स्वरूप नगर में हर कोई बसना चाहता है। नगर निगम की आय बढ़ाने हेतु भरे द्वारा घुस्सवार, स्वरूप नगर को जानी है, कहने का मतलब है कि हम पार्षद भाईयों को आपके कार्यालय में कुछ नया मिलना चाहिये। भरे बाई में जो चट्टा खुला है, मैं भी उसके शोधनी कम हो गयी है, उन्हें बदला जाये।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि पूर्व में लगी एल0ई0डी0 की रोशनी अब कम हो रही है। 02 वर्ष पूर्व ई0ई0एस0एल0 के साथ एसीमेंट में लिन एल0ई0डी0 लाईटों की रोशनी कम हो गयी है, उनके स्थान पर नयी एल0ई0डी0 लगाने की सहमति है। लिन एल0ई0डी0 की बतया है और बाई में कोई कार्य नहीं करता है। इनको जॉन से हटवाया गया था, किन्तु अभी भी वही कार्य कर रहे हैं, इसकी जाँच कराई जाये।
 श्री प्रशान्त श्रुतल ने कहा कि जॉन-2 में श्री अखिलेश तिवारी, ई0ई0एस0एल0 का कर्मचारी है, जो अपने को नगर आयुक्त का रिश्तेदार

सुश्री विधि राजपाल ने कहा कि मा० प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत हम सभी अपने-अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने में लगे हैं, किन्तु मेरे वार्ड में हाथ कूड़ा गाड़ियाँ नहीं हैं, जिसके कारण कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त है। कृपया हाथ कूड़ा गाड़ियाँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पत्रों व पत्रावलियों के रख-रखाव का सिस्टम तैयार किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, पत्र या पत्रावली जहाँ से जाये, वहीं वापस आये। शिकायतों/प्रस्तावों को श्रेणीबद्ध करते हुये समय से जवाब दिलाने हेतु एक समिति बनायेंगे। कर बढ़ाने की जो बात कही गई है, वह उचित ही है, क्योंकि जब आय बढ़ेगी तभी नगर निगम की व्यवस्था चलेगी। वर्तमान में राजस्व वसूली का लक्ष्य रू० 154 करोड़ से बढ़ाकर रू० 200 करोड़ करना है, जिसे अगले वर्ष रू० 300 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। हमारा उद्देश्य है कि करदाता बढ़े, कर की परिधि में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास है। आबकारी दुकानों से प्रतिवर्ष रू० 01 करोड़ 80 लाख की आय होना पाया गया है। 1000 हाथ कूड़ा गाड़ियों में 130 हाथ कूड़ा गाड़ियाँ वर्कशॉप में प्राप्त हो गई हैं, शेष 870 जल्द ही प्राप्त हो जायेंगी। वर्कशॉप में पड़ी 300 हाथ कूड़ा गाड़ियों के रिपेयर का आर्डर दे दिया गया है। शेष बची गाड़ियों की भी मरम्मत कराते हुये उन्हें भी उपयोग में लाया जायेगा।

श्री मो० अमीम ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में मैंने कहा था कि शहर में हाथ कूड़ा गाड़ियों की आवश्यकता है, जिस पर नगर आयुक्त द्वारा कहा गया था कि हम डोर-टू-डोर कूड़ा उठान कराने जा रहे हैं, जिससे कूड़ा गाड़ियों की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि आज हाथ कूड़ा गाड़ियों के पुनः इस्तेमाल की बात कही जा रही है। नगर आयुक्त की तब की बात सही मानी जाये या आज की। प्रत्येक वार्ड में 40-40 सफाई कर्मियों की बात कहीं गई थी, परन्तु तदनुसार तैनाती नहीं की गई। जबकि सफाई कर्मी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है।

श्रीमती शाहिबा परवीन ने कहा कि जाजमऊ दक्षिण में हाथ गाड़ी से कूड़ा उठाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वी०आई०पी० रोड, के०डी०ए० रोड में सफाई नहीं हो पाती है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि तब की बात भी सही थी और आज की बात भी सही है। हाथ कूड़ा गाड़ियों से कूड़ा उठान का कार्य किया जाता है और मौके पर जो व्यवस्था देखी गई, उसमें लगा कि नई व्यवस्था लागू होने में समय लगेगा, तब तक के लिये पुरानी व्यवस्था से ही कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में रू० 300 करोड़ का जो राजस्व वसूली का लक्ष्य बताया जा रहा है, क्या इस लक्ष्य में ओ०टी०एस० भी सम्मिलित है ? साथ ही इस लक्ष्य में सोसाइटी क्षेत्रों को भी सम्मिलित करेंगे। सोसाइटी क्षेत्र के लोग हमको टैक्स देना चाहते हैं

प्रस्तुत है :-

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा10 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-197 नवीन विज्ञापन अर्जुना शुक निवामवली लागू होने तक स्थल किराये के रूप में वर्सूली हेतु मा10 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा10 महापौर महोदयों के निर्देशानुक्रम स्वीकृति हेतु

प्रस्ताव संख्या-64

अध्यक्ष द्वारा सदन पटल पर मा10 सदस्यों द्वारा इस्तमाल गये पर्जों को पढ़ने हेतु अपर नगर आयुक्त प्रथम को निर्देश दिये गये, जिस पर अपर नगर आयुक्त प्रथम द्वारा पर्जों को पढ़ा गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से पूछा कि यदि आप सभी सहमत हो तो आपके पर्जों को जाँच कर कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त को प्रेषित कर दिया जाये। जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

स्थगित अवधि के परमाणु अपरान्त 02:30 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

अपरान्त 02:00 बजे भोजनावकाश हेतु बैठक की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित की गई।

नगर निगम को इतनाचिन्तित नहीं हुआ है।

आध्यात्मिक अभियान 'जलकल' ने अवगत कराया कि मा10 पार्क जी द्वारा जिस क्षेत्र की शिकायत की जा रही है, वह क्षेत्र आवास-विकास से

है। राजीव विहार में सीवर भरव हो रहा है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं कराई जा रही है। अनुरोध है इसकी जाँच कराई जाये।

श्री दुर्गा प्रसाद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में बार दृवबल और छः टिकिया बनी है, सभी बन्द पड़ी है, जिससे क्षेत्र की जनता पानी के लिये परेशान

की जायेगी।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मालिक या अध्यासी से नगर निगम अभियान में प्राविधानित उपकरणों/धारकों के तहत गृहकार की वर्सूली

सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का पहले निराकरण कर लिया जाये, उसके उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जाये। और हम अध्यासी से टैक्स ले भी सकते हैं, तो किस कारण से टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसके लिये कौन दायी है ? मेरा अनुरोध है कि टैक्स के

स्थल किराया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं० 13578/2018 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद सं०-354/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 में विज्ञापन कर को जी०एस०टी० के अन्तर्गत समाप्त करते हुए दिनांक 01.07.2017 से विज्ञापन कर को समाप्त करते हुए इस मद में किसी भी प्रकार की वसूली न करने तथा इसके बाद विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली वर्ष-2016 को पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में किसी भी प्रकार के विज्ञापन कर की वसूली पर रोक लगायी गयी है, जिसके कारण वर्तमान समय में विज्ञापन कर की वसूली सुनिश्चित नहीं हो सकती है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली 2016 को निरस्त करने के उपरान्त तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2017 में स्वीकृत दरों जो विज्ञापन नियमावली 2016 में अंकित दरों के अनुसार निर्धारित की गयी है, जिसका विवरण पताका-क पर अवलोकनीय है, इन निर्धारित दरों के विरुद्ध यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय से मिल कर आपत्ति की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वार्ता में यह निर्धारित हुआ था कि एसोसिएशन से वार्ता एवं सहमति के आधार पर नवीन विज्ञापन नियमावली के अन्तिम रूप से लागू होने तक आपसी सहमति से दरें निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 17.05.2019 व दिनांक 27.07.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विज्ञापन की नवीन नियमावली लागू होने तक वैकल्पिक दरों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015-16 में

निर्धारित दरों में 01.07.2017 से 31.03.2018 तक की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 50 प्रतिशत वृद्धि करने एवं इसी आधार पर पूर्व विज्ञापनपट्टी का नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया है।

उक्त के सम्बन्ध में अग्रगत करना है कि नगर आयुक्त महोदय को सम्बन्धित पत्र दिनांक 17.05.2019 द्वारा मां सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०-13578/2018 एवं मां उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०-354/2018 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करती हुए, आदेश के परिप्लव में विज्ञापन व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने हेतु नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के सम्बन्ध में यू०पी० एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मिलकर मां उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है। आदेश का क्रियान्वयन अर्थ निम्नवत है-

In view of the above after 12.09.2016 on from 01.07.2017 the Nagar Nigam, Kanpur ceased to have any jurisdiction to impose and realize tax on advertisement Accordingly the demand of tax on advertisement from the petitioners after 01.07.2017 is held to be illegal and without jurisdiction.

The notice of demand impugned in the petition to the above extent are quashed and the amount, if any of the advertisement tax deposited by the petitioners for the period 01.07.2017 onwards shall be refunded to the petitioners.

The writ petition is allowed and it is held that the Nagar Nigam, Kanpur shall not realize any tax on advertisement after 01-07-2017.

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.05.2019 के अनुसार विज्ञापन की वसूली नगर निगम द्वारा न करने एवं इसके पश्चात उक्त मद में यदि विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कोई धनराशि जमा की गई है, तो उसे वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन की वसूली किया जाना मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्भव नहीं हो पा रहा है, जबकि जुलाई 2017 से अब तक स्वीकृत विज्ञापनपट का प्रयोग निरन्तर सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता द्वारा किया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय से यू०पी० एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन द्वारा मिल कर यही अनुरोध किया गया था कि नगर निगम कानपुर की सीमान्तर्गत यदि पूर्व विज्ञापन कर के स्थान पर बनारस नगर निगम की भाँति स्थल किराया की दरें तब तक के लिए तय कर ली जायें जब तक कि नई विज्ञापन नियमावली लागू न हो जाए।

YEAR	(2016-17)	
SIZE	MET.	FIT
UNIPOLE	Rate	
SUPER	4,000.00	371.61
A	2,800.00	260.13
B	2,300.00	213.68
C	1,800.00	167.22
D	1,500.00	139.35

HORDING		
SUPER	2,500.00	232.26
A	1,700.00	157.93

2015-16				
FIT	+25%	+50%	+75%	100%
	Rate			
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00

BUS SHELT.	Rate	4,500.00	418.06
SUPER			

POLICE	Rate	4,500.00	418.06
SUPER			
A		3,500.00	325.16
B		2,500.00	232.26
C		1,500.00	139.35
D		1,000.00	92.90

CANT. L.	Rate	3,500.00	325.16
SUPER			
A		3,000.00	278.71
B		2,500.00	232.26
C		2,000.00	185.80
D		1,000.00	92.90

B		1,400.00	130.06
C		1,200.00	111.48
D		1,000.00	92.90

Rate	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
	125.00				

Rate	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

Rate	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

A	3,500.00	325.16	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

उक्त के क्रम में यू०पी०

एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा नगर आयुक्त महोदय से उक्त वार्ता के क्रम में लिखित रूप से सहमति पत्र दिनांक-17.05.2019 एवं दिनांक-27.07.2019 जो संलग्न साइड में पताका-ख व ग पर अवलोकनीय है, में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्ष 2019-20 में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत स्थल किराया तय करके वैकल्पिक शुल्क देने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में अपर नगर आयुक्त, प्रभारी अधिकारी "विज्ञापन" द्वारा यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से वित्तीय वर्ष में प्रचलित दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी कर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दरें तय कर ली जाए। ऐसा करने से विज्ञापन की दरें जो अब (स्थल किराया) में लिया जाना है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 की दरों से अधिक हो जाएगी। उपरोक्त यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन को स्वीकार नहीं है। यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा विज्ञापन दरों में वृद्धि का जो प्रस्ताव दिया है वह निम्नवत है:-

01. मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुरूप 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है।
02. चूँकि वर्तमान में विज्ञापन नियमावली निरस्त है एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना विधिक प्रावधान के किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है और 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में ली गई धनराशि वापस करने का भी आदेश है।
03. 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं के मध्य स्थल किराया वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रचलित दरों के आधार पर दरें तय कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृताएँ प्रेषित है।

2017 से नवीन विज्ञान नियमावली लागू होने तक उक्त अनुसार स्थल किराया को स्वीकृति एवं अग्रिम आदेशार्थ आख्या प्रेषित है। किराया तत्काल नगर निगम कोष में जमा करना होगा। कृपया नगर निगम वित्तीय हित में नगर में जगे सभी स्वीकृत विज्ञानपट्टों से 01.07. समाधान बनना तो वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 पर लागू नहीं होगा एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की नवीनीकरण एवं निर्धारित स्थल जाता है तो यह प्रतिबन्ध रहेगा कि जमा की गयी धनराशि में यदि किसी भी विज्ञान एजेंसी का जमा की जाने वाली धनराशि में यदि कोई पूर्ण हो सकती, जिससे नगर निगम राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना होगी। यदि विज्ञान एजेंसियों के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया विज्ञान नियमावली लागू होने तक बर्सेली करने का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही विज्ञान एजेंसियों के नवीनीकरण/पूनीकरण की प्रक्रिया विज्ञानकर्ताओं से 01.07.2017 से 31.03.2019 तक पूर्व प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं 01.04.2019 से 50 प्रतिशत वृद्धि नवीन मद में जमा की गई धनराशि वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथ ही 01.07.2017 से नवीन विज्ञान नियमावली लागू होने तक जिसका विवरण पूर्व में वर्णित किया गया है की भी अवमानना नहीं होगी, साथ ही नगर निगम विज्ञानकर्ताओं 01.07.2017 के बाद विज्ञान निरसे मां सर्वोच्च न्यायालय में याचित बाद सं०-13578/2018 एवं मां उच्च न्यायालय में याचित बाद सं०-354/2018 के आदेश, 2017 के पश्चात नगर में स्वीकृत विज्ञानपट्टों से स्थल किराया का प्रस्ताव यू०पी० एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों से लिखित रूप से आया है, था, इन दरों पर विज्ञान कर की समाप्ति उपरान्त स्थल किराया के रूप में उक्त दरों को स्वीकार करने पर सहमत नहीं है। चूंकि 01.07. जिसके विरुद्ध मां न्यायालय में बाद दाखिल किया था और मां न्यायालय द्वारा विज्ञान नियमावली-2016 को निष्प्रभावी कर दिया गया नगर आर्युक्त महोदय के आदेश दिनांक-24.11.2017 में निर्धारित दरें विज्ञान नियमावली 2016 के अनुसार निर्धारित की गयी थी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रचलित दरों में प्रचलित दरों में प्रतिशत अनुसार वृद्धि निम्नवत है-

नगर आयुक्त ने कहा कि हम जो बॉयलॉज बना रहे हैं, उसको 20 श्रेणियों में बाँटा जा रहा है। वर्तमान में विज्ञापन मद से नगर निगम को कोई आय नहीं हो रही है। मैं जहाँ भी निकल रहा हूँ वहाँ पर यदि कोई अनधिकृत होर्डिंग दिखती है तो उसको हटवा कर मैं स्वच्छ भारत मिशन की होर्डिंग्स लगवा रहा हूँ।

सदस्यों ने कहा कि महानगर के अन्तर्गत वैध होर्डिंग्स की अपेक्षा अवैध होर्डिंग्स की संख्या अधिक है। हमारे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कौन सी होर्डिंग वैध है और कौन सी अवैध ?

नगर आयुक्त ने प्रभारी अधिकारी विज्ञापन को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक पार्श्व को जोन स्थित उनके वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत वैध होर्डिंग्स की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

श्री स्वर्ण सिंह, प्रभारी अधिकारी विज्ञापन ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 विज्ञापन में कोई आय प्राप्त नहीं हुई है, विज्ञापन एजेन्सियों से स्थल किराये के प्रस्ताव पर सहमति आई है।

अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापन के प्रस्ताव को पिछली बकाया धनराशि की वसूली हेतु स्वीकृत माना जाये साथ ही आश्वस्त करती हूँ कि कानपुर महानगर को होर्डिंग मुक्त किया जायेगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि कानपुर नगर को होर्डिंग्स मुक्त करने की जहाँ तक बात है, इसके सापेक्ष कहना है कि 20 तरह के विज्ञापन पट हैं। सुझाव है कि उसमें एक समिति बना दी जाये, समिति की जो कार्य योजना बनेगी, उसे अपनाया जायेगा। पूर्व में विज्ञापन जो बिना बाईलाज के चलता रहा और बाई लॉज बनने के बाद उसके अनुसार विज्ञापन स्थल किराया वसूली की जा सकेगी। अध्यक्ष ने कहा कि होर्डिंग्स मुक्त करने के बारे में विचार किया जाये, परन्तु उसके पूर्व एक वर्ष तक देख लिया जाये कि इस प्रस्ताव से कितना धन आ रहा है।

हाजी सुहैल ने कहा कि पार्श्वदो के माध्यम से विज्ञापन दरों पर आपत्ति मांगी गयी थी, जिनमें पार्श्वदो ने 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक एवं दिनांक 01.04.2019 से 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर विज्ञापन कर वसूलने का सुझाव दिया गया था।

मॉडल पर दे दिया जाये, तो काफी धन आयेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि उक्त धर्मशाला का भेरे द्वारा अवलोकन किया गया है, नगर निगम द्वारा काफी अच्छा बनाया गया है, इसे पीओपीओ

कैसे दे सकता है?

श्री महेश सुबला 'दत्ता' ने कहा कि भेरे वार्ड में धर्मशाला है, उसका ब्यूल्क 25 हजार कर दिया गया है, गरीब आदमी इतना धन

स्वीकृति प्रदान की गई।

..... मन्दी चौक, बालाजुकुलित एवं साधारण सिनेमाघरों की संशोधित दरें कमरा: रु० 100/-, रु० 40/- - तथा रु० 40/- प्रति घंटा की वर्सूली हेतु

चौक, बालाजुकुलित एवं साधारण सिनेमाघरों की संशोधित दरें कमरा: रु० 100/-, रु० 40/- - तथा रु० 40/- प्रति घंटा पर सहमति बनी है।

गई। मा० महापौर महोदय द्वारा कानपुर सिनेमा एक्जीबीशन कंप्लेक्स, कानपुर के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें विचार-विमर्श उपरान्त मन्दी

के पदाधिकारियों द्वारा मा० महापौर जी को सम्बोधित पत्र में दरों की वृद्धि पर उपापत्ति प्रस्तुत की

सिनेमाघरों की दरें कमरा: रु० 600/-, रु० 300/- - तथा रु० 100/- प्रति घंटा निश्चित की गई थी, जिस पर कानपुर सिनेमा एक्जीबीशन कंप्लेक्स, कानपुर

मा० सदर की बैठक दिनांक 05.12.2018 के प्रस्ताव संख्या-42 द्वारा श्री-टैक्स रु० 20/- के स्थान पर मन्दी चौक तथा साधारण

रु० 20/- कर दर से श्री टैक्स विगत कई वर्षों से लिया जा रहा है, और उसमें कोई बदलाव नहीं की गई है।

कानपुर नगर निगम सीमान्तगत आने वाले प्रभागों से नगर निगम अधिनियम की धारा-172 की उपधारा(2)(ख) के अधीन विभिन्न प्रभागों से प्रति घंटा

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय पत्रांक 461/3/प दिनांक 10.07.2019 के मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-65

प्रतिशत वृद्धि एवं 01.04.2019 से 60 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्थल किराया वर्सूली करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

..... 01.04.2016 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक विज्ञापनकरताओं से 31.03.2019 तक पूर्व प्रचलित दरों में 40

कर वर्सूला जायेगा।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पार्षदों के संज्ञाव के अनुसार 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अनुसार ही विज्ञापन

प्रस्ताव संख्या –66

दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या-172 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

उद्यान अधीक्षक, पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत, अपर नगर आयुक्त द्वारा समर्थित एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-**मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में प्रवेश शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में**

मोतीझील स्थित कारगिल पार्क शहर का महत्वपूर्ण पार्क है। हरियालीयुक्त स्वस्थ पर्यावरण के साथ झील, स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा, झूले क्यास्क का लाभ शहर के नागरिकों के साथ-साथ अन्य शहर के आने वाले गणमान्य नागरिक एवं बच्चे भी प्राप्त करते हैं। पार्क में प्रवेश शुल्क दर 5 रु. प्रति व्यक्ति, 3 रु. प्रति बच्चा (3 वर्ष से 12 वर्ष तक) निर्धारित है। साथ ही साथ गार्निंग/ईवनिंग वाकर्स जो प्रतिदिन कारगिल पार्क के स्वस्थ पर्यावरण का लाभ प्राप्त करते हैं, हेतु 30 रु. प्रतिमाह अथवा 300 रु. प्रति वर्ष पास दर निर्धारित है। उक्त दरें अत्यन्त ही कम हैं। जबकि मोतीझील स्थित के.डी.ए. के बाल उद्यान पार्क में प्रवेश शुल्क 15 रु. प्रति व्यक्ति है। उक्त के दृष्टिगत मोतीझील स्थित कारगिल पार्क का प्रवेश शुल्क मासिक/वार्षिक पास दर निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

10 (दस) रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

5 (पाँच) रु. प्रति बच्चा (3 वर्ष से 12 वर्ष) प्रतिदिन।

45 (पैंतालिस) रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह अथवा 450 (चार सौ पचास) रु. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

अतः मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित प्रवेश शुल्क, मासिक/वार्षिक पास दर लागू किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या –67

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-176 को स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

विषय	जुमाने की वर्तमान दरें	जुमाने की प्रस्तावित दरें
------	------------------------	---------------------------

कनपुर नगर निगम सीमान्तगत पशु पालकों द्वारा अपने गाँवों को छूट्टा छोड़ दिव्य जाने से आम नागरिकों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने हेतु शासन के निर्देशानुपालन में निराश्रित/बेसहारा पशुओं को पकड़कर 01-कान्हा गाँवपाल, जामा गाँव, जाममऊ 02-गौ अष्टारवा, पनकी 03-अरुआई गौ सरक्षण केन्द्र, बकरमण्डौ 04-कौली हाउस, दर्शनपुरवा 05-कौली हाउस, जाममऊ में निरूद्ध किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा 21 से 26 व 41 के अन्तर्गत पशुपालकों से एवं उपरोक्त स्थलों में निरूद्ध किये जाने वाले जानवरों के स्वामियों से जुमाना बसूली के लिये पूर्व में मा10 नगर निगम सदन की सम्मन हुई थी बैठक दिनांक-01.09.2016 द्वारा दरों में बदलावों की गयी थी। उक्त बढी दरें 01.09.2016 के बाद से प्रभावी हैं, वर्तमान में महंगाई दरों की वृद्धि के दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रस्तावित दरें मा10 कार्यकारणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं :-

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्ताव निम्नवत है:-

नगर आर्यवत महोदय द्वारा अनुमोदित एवं मा10 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

से प्रस्तुत करने के लिये मा10 महापौर महोदयों के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

दिनांक 08.11.2019 को सम्मन हुई मा10 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-202 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा10 सदन की बैठक

प्रस्ताव संख्या-68

..... तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्तर्गत आनुरोध अण के रूप में प्राप्त करने हेतु मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित धनराशि को 260.00 लाख एवं दीनदयाल उपखण्ड नगरीय विकास योजना के विभिन्न धर्मों में विकास कार्य हेतु को 260.00 लाख के कार्यों की सैद्धान्तिक समिति उत्तर प्रदत्त शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

मा10 श्री अरुण पाटक, सदस्य, विमान परिषद, 2000 द्वारा प्रेषित एवं दीन दयाल उपखण्ड नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत सड़क के

देशी/संकर नरल की गाय, भैंस, घोड़ा एवं खच्चर आदि	रु0 1000.00 प्रति पशु	रु0 5000.00 प्रति पशु
गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर के बच्चे एवं सुअर आदि	रु0 1000.00 प्रति पशु	रु0 2500.00 प्रति पशु
सभी पशुओं/जानवरों की प्रतिदिन की खुराकी	रु0 150.00 प्रति पशु	रु0 150.00 प्रति पशु

.....जानवरों के स्वामियों से वसूली जाने वाली उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दरों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या-69

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-194 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में विचारार्थ/स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

कार्यालय पत्र संख्या----- दिनांक----- की अधिनियम की धारा----- के अन्तर्गत सूचनार्थ पढना/स्वीकृति प्रदान करना/स्वीकृति हेतु नगर निगम से अनुशंसा प्रदान करना-

14 वें वित्त आयोग के अनुदान से मोबाइल टॉयलेट(10 सीटर) क्रय किये गये है। जिनकी आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। जिनका सदुपयोग बाढ राहत शिविर एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमो के आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। क्रय किये गये मोबाइल टवाइलेट की सार्वजनिक/घार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में मॉग को दृष्टिगत रखते हुये उक्त के सुचारु रूप से संचालन हेतु किराये का निर्धारण क्रय किये गये मोबाइल टॉयलेट की सार्वजनिक कार्यक्रमों/घार्मिक कार्यक्रमों एवं जन सामान्य से जुडे अन्य कार्यक्रमो में निकट भविष्य में मॉग आने की सम्भावना है। मोबाइल टॉयलेट की मॉग आने पर ट्रैक्टर के माध्यम से भेजना पडेगा, जिसमें डीजल आदि का व्यय भार नगर निगम पर पडेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि किराये पर लेने वाली संस्था उपकरण का उपयोग उचित प्रकार से करें, जिससे उपकरण को कोई क्षति न पहुचें, इसलिये आवश्यक है कि उपकरण को किराये पर देने से पूर्व किराये पर लेने वाले संस्था/व्यक्ति से रु0 10,000.00(रुपया दस हजार मात्र) जमानति धनराशि के रूप में जमा करा लिया जायें। जिसे उपकरण के यथा स्थिति में वापस प्राप्त होने की दशा में वापस कर

प्रस्ताव संख्या-70

समाप्ति नै कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोग हेतु रियायत दी जानी चाहिये।
मोबाइल टैरिफ्टस उपयोग हेतु उपरोक्तानुसार वार्षिक दरों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

की सम्माननायें अधिक रहती है।

श्री भी० अमीन व अन्य सदस्यों ने कहा कि मोबाइल टैरिफ्टस का प्रयोग ज्यादातर बड़े-बड़े कार्यक्रमों व शादी-समारोह में किया जाता है, जिसमें टैट-फूट जाये वनसे यह जानकारी कर ली जाये कि कितने व्यक्ति इसका प्रयोग करेंगे।
 नगर आयुक्त ने कहा कि जो मोबाइल टैरिफ्टस ले जाते हैं, वह आर्थिक रूप से मजबूत हैं जो यह जमानती धनराशि उचित है। जो भी मोबाइल टैरिफ्टस ले नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त ज्यादातर मोबाइल टैरिफ्टस क्षतिग्रस्त होकर वापस आते हैं।

तथा टैरिफ्ट को नुकसान भी हुआ है ?

नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि एक टैरिफ्ट की कीमत क्या है ? और क्या पूर्व में मोबाइल टैरिफ्ट सार्वजनिक उपयोग हेतु दिये गये हैं प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मोबाइल टैरिफ्ट के किराये एवं आने जाने में खर्च होने वाले इंधन के व्यय के निर्धारण हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष

दृष्टी	विवरण	जमानति धनराशि		
		दैनिक	किराया	इंधन पर आने वाला व्यय
01 से 05 किमी० तक	मोबाइल टैरिफ्ट को भेज जाने व वापस आने हेतु	3,000.00	300.00	3,300.00
05 से 10 किमी० तक	मोबाइल टैरिफ्ट को भेज जाने व वापस आने हेतु	3,000.00	600.00	3,600.00
10 से 15 किमी० तक	मोबाइल टैरिफ्ट को भेज जाने व वापस आने हेतु	3,000.00	900.00	3,900.00
15 से 20 किमी० तक	मोबाइल टैरिफ्ट को भेज जाने व वापस आने हेतु	3,000.00	1,200.00	4,200.00
20 से 25 किमी० तक	मोबाइल टैरिफ्ट को भेज जाने व वापस आने हेतु	3,000.00	1,800.00	4,800.00
			किराया	
			इंधन पर आने	
			कुल योग	

वाले इंधन के व्यय का निम्नानुसार निर्धारण किया जाने का प्रस्ताव निम्नवत है:-

दिया जायेगा। मोबाइल टैरिफ्ट का उपयोग स्यूचारु रूप से होता रहे, इसलिये प्रति दिन की दर से किराये एवं आने जाने में खर्च होने

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-195 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में विचारार्थ/स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 36666/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 व अवमानना याचिका संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के बढ़े हुए किराये के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित है।

प्रस्ताव

विषय- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 36666/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 व अवमानना याचिका संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित

आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों का किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 समिति को अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 16.01.2013 को मा0 कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 47,83 व 84 द्वारा विभिन्न जोंनों में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के किराये में वृद्धि विषयक प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किये गये थे एवं मा0 सदन की बैठक दिनांक 16.02.2013 में क्रमशः प्रस्ताव संख्या 29,36 व 37 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप किराये की दरों में वृद्धि करते हुए दिनांक 01.03.2013 को प्रभावी किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के क्रम में विभिन्न आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगभग 21 रिट याचिकाओं के माध्यम से नगर निगम की किराये की सम्पत्तियों के किराया वृद्धि को चुनौती दी गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा मूल रिट याचिका संख्या 36666/2013 के साथ अन्य रिट याचिकाओं को संकलित (CLUB) करके एक निर्णय दिनांक 13.12.2013 को पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

In the totality of the circumstances on record, we dispose of these writ petitions with a direction to the Munciple Commissioner to examine the grievance of the petitioners in the matter of enhancement of the rent and to decide the same by means of a reasoned and speaking order, preferably within a period of two months from the date a certified copy of this order is filled by the petitioners. If required he may place the matter again before the Executive Committee of the Nagar Nigam.

We make it clear that till the decision of the representation by the Nagar Ayukta/Executive Committee, the petitioners shall continue to pay the rent as fixed by the Nagar Nigam. Such deposit shall be subject to the order to be passed by the Nagar Ayukta as aforesaid.

We the aforesaid directions, all the writ petitions are disposed of.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के क्रम में उक्त क्रियात्मक अंश को मा0 कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 30.08.2014 में प्रस्ताव संख्या 669 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में किरायेदारों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनो के

निस्सारण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। उपर्युक्त स्वीकृति के क्रम में तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश संख्या 338/3/प दिनांक 22.06.2015 द्वारा अग्र नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रभावी अधिकाधिकारी सम्मिलित एवं समस्त जनल अधिकाधिकारियों को सदस्य नामित कर विभिन्न किरायेदारों द्वारा दी गयी आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए एक समिति का गठन किया गया। आवंटियों द्वारा मांग उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बर्दा हुआ किराया न जमा करने के कारण गठित समिति द्वारा दिनांक 25.08.2015 को सब समिति से यह मत स्थिर किया गया कि "मांग न्यायालय के आदेशानुसार सहायित किरायेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित किराया जमा नहीं करता है तो प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना उचित नहीं है।"

मांगकर्ता जी एवं तत्कालीन नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के किराये पर उठी सम्पत्तियों के किराये के सम्बन्ध में मांग कर्ताओं की सम्मति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय होने तक उसका किराया पाट्टे भेजने के क्रम में जमा कराये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक डी/320/सम्पत्ति/15-16 दिनांक 02.02.2016 समस्त जनल अधिकाधिकारियों को निर्णय किया गया है। मांग उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 13.12.2013 में प्रकरण को निरस्त करने की सलाह प्रदान की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित श्री रामेश्वर सिंह व 15 अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 20356/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 निम्नवत् है-

Counsel for the petitioners does not press the writ petition and submits that the petitioners shall deposit the arrears of rent, as per the order dated 4.2.2016 and shall continue to pay the rent as per the said order till the petitioners' grievance in the matter of enhancement of rent, is decided finally by the Municipal Commissioner, as per the order dated 13.12.2013 passed in Civil Misc. Writ Petition No. 36666 of 2013. His statement is recorded and accepted.

Counsel for respondents-authority submits that the Municipal Commissioner shall endeavour to decide the petitioners' representation, as per the aforesaid order, as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from the date of receipt of this order. The petitioners are directed to produce a copy of this order along with a copy of the writ petition and annexures before the Municipal Commissioner within 10 days from today.

The petition is, accordingly, disposed of."

इस प्रकार उपरोक्त रिट याचिका संख्या 36666/2013 व रिट याचिका संख्या 20356/2018 व 18638/2018 में पारित आदेश का गठन न होने के कारण अवमानना याद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अवमानना याद संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 निम्नवत् है-

"Counsel for the petitioners does not press the writ petition and submits that the petitioners shall deposit the arrears of the rent, as per the order dated 4.2.2016, till today and shall continue to pay the rent as per the said order till the petitioners' grievance in the matter of enhancement of rent, is decided finally by the Municipal Commissioner, as per the order dated 13.12.2013 passed in Civil Misc. Writ Petition No. 36666 of 2013. His statement is recorded and accepted.

Counsel for respondents-authority submits that the Municipal Commissioner shall endeavour to decide the petitioners' representation, as per the aforesaid order, as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from the date of receipt of this order. The petitioners are directed to produce a copy of this order along with a copy of the writ petition and annexures before the Municipal Commissioner within 10 days from today.

The petition is, accordingly, disposed of."

Learned counsel for the applicants submits that a certified copy of the aforesaid order was submitted for compliance before the opposite party but the opposite party has wilfully not complied with the order and, thus, has committed civil contempt liable for punishment under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.

Prima facie a case of contempt has been made out. However, considering the facts and circumstances of the case, one more opportunity is afforded to the opposite party to comply with the aforesaid order of the Court within two months from the date of production of a certified copy of this order.

The applicants shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite party and another self-addressed stamped envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within one week thereafter and keep a recorded thereof.

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate him of the order through the self-addressed envelope within a week thereafter.

With the aforesaid observations, this application is disposed of at this stage with liberty to the applicants to move a fresh application, if the order is not complied with by the opposite party within the stipulated time as aforementioned.

प्रकरण के निस्तारण हेतु मेरे आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा नयी समिति गठित की गयी व उपरोक्त उल्लिखित रिट याचिकाओं/अवमाननावाद में पारित आदेशों के क्रम में जोनो में प्राप्त करायी गयी आपत्ति/प्रत्यावेदनो का परीक्षण किया गया, जिसमें याचीगणो द्वारा निम्न आधार पर आपत्तियां की गयी कि शासनादेश दिनांक 01.09.1977 के तहत हर पांच वर्ष में बढ़े हुए दर से किराया जमा कराये जाने, (2) अधिकतम देय किराये में कमी करने, (3) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यथोचित आदेश पारित करने, (4) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने, (5) किराया निर्धारण हेतु शासन को प्रत्यावेदन अन्तरित करने, (6) किराया बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में 1970 एवं 1987 में समझौते के आधार पर किराया निर्धारण करने, (7) विचार कर किराया संसोधन करने, (8) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उचित किराया निर्धारित किये जाने, (9) सभी दुकानदारो का किराया पूर्व की भांति प्रत्येक पांच वर्ष पर 12½% बढ़ाकर निर्धारित करने, (10) किराया न्याय संगत न होने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा नगर निगम सम्पत्तियों के किराये वृद्धि विषयक शासनादेश संख्या 3366(2)-जे/11-न0पा0 -4-1ए(4)/77 दिनांक 01 सितम्बर 1977 के बिन्दु 02 को संज्ञान में लेते हुए प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया, बिन्दु 02 निम्नवत है:-

"स्थानीय निकायों ने अपनी दुकानों और भवनों आदि की जो सम्पत्तियां किराये पर उठा रखी हैं, उनके सम्बन्ध में भी यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि उनका किराया और प्रीमियम अत्यन्त कम हैं और किराये की धनराशि लम्बे समय से पुनरीक्षित नहीं की गयी है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्तियों का किराया वर्तमान बाजार दर के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाये, ताकि स्थानीय निकाय ऐसी सम्पत्तियों का भली-भांति रख रखाव करने के साथ-साथ अपनी आय में भी यथोचित वृद्धि कर सके।"

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन के साथ निर्धारित किराये की दरों में दिनांक 01 सितम्बर 1977 को जारी शासनादेश क्रमांक 3366(2)-जे/11-न0पा0-4-1ए(4)/77 के अनुपालन के क्रम में प्रत्येक पाँच वर्ष में किराये में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही है जो कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये से बहुत कम है। वर्ष 2013 में मा0 नगर निगम सदन द्वारा पुर्ननिर्धारण करते हुए वृद्धि की गयी। इस प्रकार शासनादेश सं 406/नौ-9-1997-95 जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 में शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय जिसमें स्थानीय निकायों द्वारा अपनी सम्पत्तियों (दुकानों)

साहित्य वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान में 110 बाउंडेड डॉर कूड़ा कलेक्शन का कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। डॉर टू डॉर प्रणाली को बर्खास्त करने के लिए 110 बाउंडेड डॉर कूड़ा कलेक्शन एवं अनावसीय स्थानीय/प्रति परिवार/गहन स्थानों से की जाती है। अनावक करना है कि पूर्व से संकोचीन नगर

में विद्यार्थ/स्वीकृत्य हेतु प्रस्तुत है :-

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या-196 को स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन की बैठक

प्रस्ताव संख्या -71

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा राखे हुए डॉर टू डॉर प्रणाली को अग्रीम स्वीकृति प्रदान कर दी जाये, यदि भविष्य में इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना होगा, तो उसे मा0 कार्यकारिणी के समक्ष रख कर स्वीकृत करा लिया जायेगा। यदि इस प्रस्ताव को अग्रीम स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो बांधा काफी समय बाद यह प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत हो पायेगा, अतः इसे स्वीकृत प्रदान किया जाना उचित होगा साथ ही आवश्यक करता है कि नगर निगम की आय में वृद्धि होने से समय से कर्मचारियों को देयकों का भुगतान तथा धीमा में सम्पत्ति विकास कार्य भी कराये जा सकें।

समाप्ति ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से अपने अधिकारियों से पूछना चाहती है कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत हमारी नगर निगम की कितनी टुकड़ें हैं और उनसे कितना किया जा सकता है। पहले सभी सदस्य इस पर चर्चा करें।

माननीय कार्यकारिणी समिति/सदन में विद्यार्थ/निर्धन हेतु प्रस्तुत है।
निगम की आय में वृद्धि को सञ्चालन में लेने हेतु बलहीन पायी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रस्ताव अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकारियों की आपत्तियां शासन/देश संख्या 406/नौ-9-1997-95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 व नगर मा0 वृद्धि पूर्णतया नियमानुसार व यथावित्त है।
द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2013 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया दर के कारण नगर निगमों द्वारा आय के संसाधन में वृद्धि किया जाना अभी तक हो गया था। ऐसी स्थिति में किये में की हेतु निर्धारित किया गया था। वर्ष 2013 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया दर के 50% की वृद्धि की गयी। उत्तरखण्ड है कि इस बार वर्ष में जिलाधिकारी तदनुसार शासन/देश संख्या 406/नौ-9-1997-95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 में बाजार दर के आधार पर आय में वृद्धि हेतु किया निर्धारण धरणी में वृद्धि का निर्णय मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया, जो समस्त परिस्थितियों के आलोक में उचित एवं यथावित्त प्रतीत होता है।
आदि का किया बाजार दर पर निर्धारित करने का उल्लेख है। उक्त के कम में जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा निर्धारित सर्कल रेट का 1/2 किया

नगर आयुक्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। अभी हमारे पास यह डेटाबेस नहीं था कि यदि हमने किसी क्षेत्र में 05 सफाई कर्मियों को कूड़ा कलेक्शन के लिये लगाया है तो यह निश्चित नहीं हो पाता था कि वह 05 सफाई कर्मचारी पूरे क्षेत्र का कूड़ा ले पायेंगे या नहीं। अभी हम यह दिखवा रहे हैं कि वार्ड में कितने घर हैं, तदनुसार ही मानव बल लगाये जायेंगे तथा सेवाप्रदाता कम्पनी एवं नगर निगम की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि वार्ड के भवनों के हिसाब से सफाई कर्मी लगाये जाये तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाये।

.....प्रतिमाह प्रश्नगत यूजर चार्ज वसूली की प्रस्तावित दरों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष को निम्नवत हस्तगत प्रस्तावों पर विचार किया जाना।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-72

श्री जमाल, नाजिरबाग, बेकनगंज बाजार आवासीय संघ, 98/179, बेकनगंज, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना-

विषय :बेकनगंज में नगर महापालिका की जमीन पर अवैध कब्जों को खाली कराकर पी0पी0पी0 मॉडल पर बाजार विकसित कराये जाने हेतु मा0 में।

बेकनगंज में नगर महापालिका की जमीन पर अवैध रूप से गूदड़ बस्ती है, जिस पर किसी समय बाजार भी लगता था। उक्त जमीन नगर महापालिका की है। यदि नगर महापालिका की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाकर पी0पी0पी0 मॉडल पर बाजार विकसित किया जाये, तो वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उच्च होगा, क्षेत्र भी काफी स्वच्छ एवं सुन्दर होगा, साथ ही नगर निगम को काफी राजस्व प्राप्त होगा।

अतएव बेकनगंज में नगर महापालिका की जमीन पर स्थित गूदड़ बस्ती को हटाकर पी0पी0पी0 मॉडल पर बाजार विकसित किये जाने हेतु टेबुल प्रस्ताव मा0 सदन के विचारार्थ /स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.....नगर आयुक्त को परीक्षण कराते हुये परीक्षण आख्या अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

अतः उपरोक्त आवासीय/अवासीय भूजल गांव की दरें पुनरीक्षण की स्वीकृति फिरे जाने हेतु मांग कारकादिवाणी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव है।

भूमी का विवरण	उप विधि के अनुसार प्रस्तावित दर (रुपया) प्रतिमाह	निर्धारित दरें (रुपया) प्रतिमाह/प्रति परिवार	प्रस्तावित दरें (रुपया) प्रतिपरिवार
आवासीय बी.पी.एन. गलिन बस्ती, 30 वर्ग मी० तक	30-40 प्रति परिवार प्रतिमाह	10	25
आवासीय 15 वर्ग मी० क्षेत्रफल तक			
अन्य आवासीय	30-40 प्रति परिवार प्रतिमाह	30	50
आवासीय-एल.आइ.बी.ग्रुप/क्षेत्रफल	30-40 प्रति परिवार प्रतिमाह	50	100
आवासीय/हाउसिंग सोसाइटीज	40-50 प्रति परिवार प्रतिमाह	50 प्रति फ्लॉट/प्रति परिवार	100
आवासीय-20 वर्ग मी० तक रुकान	30 रुपया प्रतिमाह दर	30	100
आवासीय 20 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल की	रुकान/काधान		
शैलिक दर्याना, प्रडक्ट कॉमिंग दर्याना, नरिंग हांग, धरौल पम्प आदि	रु० 2 से 2.50 धर्याना प्रति वर्ग मी० आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संख्या	500	600
सरकारी कार्यालय, भवन, शौचालय, मकान (20 रुकानों से अधिक गैर हाउस, आडिटोरियम, हाउस, बीक, हाउस, बकट हांग, कनव, सिनेमा हांग, फूट, अस्पताल, विश्वविद्यालय, शैलिक दर्याना, शैलिक कांजंग, कामाक्षीयल गांग 1000 वर्ग मी० से अधिक	रु० 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी० आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संख्या	1000	1250
1000 वर्ग मी० आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक	रु० 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी० आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संख्या	5000	6000

अनुपम महेन्द्र के आदेश मां 103/प्रोडक्ट रीज दिनांक 13.07.2011 के अनुसार ए.इ.डी.डि.इ.कार्डकर मां 101/10 को निम्नानुसार प्रकार गांव गांव वसुली के आदेश दिवे गये है। वर्तमान में वसुली दरों से निम्नानुसार पुनरीक्षण दरें प्रस्तावित है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-73

विषय : कानपुर शहर के विभिन्न पार्कों में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों का संचालन एवं रख-रखाव का अधिकार नगर निगम के अधीन लिये जाने हेतु मा0 सदन हेतु टेबुल प्रस्ताव।

कृपया कानपुर शहर के कॉलोनियों एवं अन्य क्षेत्रों में पार्क बनाये गये थे, ताकि आस-पास के निवासियों को शुद्ध हवा, हरित क्षेत्र, बच्चों को खेलने, वृद्धों को टहलने हेतु स्थान मिल सके साथ ही खुले क्षेत्र में रेन वाटर से जमीन के अन्दर का पानी रिचार्ज हो सके, किन्तु विभिन्न पार्कों में अवैध रूप से बिना नगर निगम की स्वीकृति के धार्मिक स्थलों का निर्माण कर दिया गया है। कई धार्मिक स्थलों द्वारा लगातार पार्कों में विस्तार किये जा रहे हैं, जिससे हरित क्षेत्र समाप्त हो रहा है एवं समाप्त होने की आशंका है। जिससे भविष्य में आस-पास के निवासियों को शुद्ध हवा, बच्चों के खेलने के स्थान, रेन वाटर रिचार्ज न होने जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

अतएव कानपुर शहर के विभिन्न पार्कों में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों के संचालन एवं उसके रख-रखाव का अधिकार नगर निगम के अधीन लिये जाने हेतु टेबुल प्रस्ताव मा0 सदन के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ अग्रसारित है।

.....मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-74

विषय : गंगा बैराज स्थित अटल घाट एवं 128 सालो बाद बन्द सीसामऊ नाले को आकर्षक बनाते हुए सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 सदन के टेबुल प्रस्ताव

कृपया श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के फलस्वरूप नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत कानपुर में विगत 128 वर्षों से अनवरत गंगा में गिर रहे नाले को बन्द किया गया है, साथ ही गंगा बैराज पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम पर अटल घाट का विकास किया गया है। उक्त बन्द सीसामऊ नाले एवं अटल घाट को सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किया जाये तो कानपुर में एक नये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।

अतएव अटल घाट एवं बन्द सीसामऊ नाले को सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 सदन के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अतएव अटल घाट एवं बन्द सीसामऊ नाले को सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 सदन के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.....स्वीकृति प्रदान की गयी।

1. पहाड़पुर गांव की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।
2. बार्ड-82 कस्टडी सब स्टेशन से निहारिका हाथियरल होते हुये हाईटेन्शन रोड तक भाग का निर्माण कार्य। (हाईवे मार्ग)

निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ मा10 सदन के समक्ष प्रस्तुत है :-

आतः जनहित में निम्न 22 सड़कें, जोकि अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं, के निर्माण/मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु हो पा रहा है।
 धन व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण इनका निर्माण/मरम्मत कराया जाना संभव नहीं है।
 क्षेत्र की जनता द्वारा इनके निर्माण/मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता है। चूंकि यह सड़कें निर्माण योग्य हैं, जिसमें काफी कष्टों का नगर निगम की अन्तर्गत नव विकसित कॉलोनियों की सड़कें एवं उसके समर्क मार्ग अत्यधिक जबर अवस्था में हैं। प्रायः उस

टैबल प्रस्ताव संख्या-76

.....तदनुसार उपरोक्त दोनों सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

आयुक्त ने दोनों सड़कों को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुमोदित कर दिया है।
 जिनका नगर निगम निर्माण/मरम्मत नहीं करा पा रहा है, प्रस्ताव तैयार कर नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्सम्बन्ध नगर कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या-184, जिसमें स्वीकृत करते हुए सदन को अधिसारित किया गया है कि ऐसी सड़कों को

समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

तकम में उपरोक्तानुसार दोनों सड़कों को लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2 कानपुर नगर को हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा10 सदन के

2. जोन-3 बार्ड-39 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर में बाकरगंज चौराहा से वृद्धी नहरिया तक (150 फिट)।

1. जोन-3 बार्ड-39 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर में नयागुल से कैनाल रोड तक (100 फिट)।

दिनांक 28.08.2019 के द्वारा जोन-3 की निम्न सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-
 निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, कानपुर नगर के पत्र सं10-234 दिनांक 17.09.2019, जिसमें शासन के पत्रांक-1401सा10/23-1219-03सा10/19 दिनांक 08.11.2019 को मा10 कार्यकारिणी समिति की सम्मन हुई बैठक में मा10 सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न 02 सड़कों को लोक

टैबल प्रस्ताव संख्या-75

3. वार्ड-46 सतवरी गाँव की आन्तरिक गलियों में मार्ग निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
4. वार्ड-46 गोपाल नगर बाईपास कृष्णा धर्म कौटा से त्रिवेणी शंकर मिश्रा व आस-पास की गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
5. कृष्णा वाटिका लॉन के बगल व पीछे की गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
6. आवास-विकास वार्ड-41 सेक्टर 6ए व 7 से चण्डीपुरवा व मुख्य मार्ग एवं आस-पास की गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
7. वार्ड-68 प्लॉट नं0-4 रामकृपाल शर्मा के घर से प्लॉट नं0-1153बी जगदीश शर्मा के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
8. वार्ड-68 मकान नं0-128/27 प्रेम के घर से युसुफ के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
9. वार्ड-22 लालपुर बस्ती सुभाष दुबे से अश्वनी वाजपेई के घर होते हुये उमाशंकर के मकान व दयालपुर रोड दयालपुरम में रामचन्द्र के घर होते हुये हाईटेंशन रोड तिलम्बी गाँव तथा उदयवीर के घर से पंचवटी मन्दिर का कार्य। (शहरी मार्ग)
10. वार्ड-21 भैयादीन अमीन के घर होते हुये अवधेश शुक्ला के घर से ट्रान्सफार्मर तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
11. वार्ड-82 रामगोपाल चौराहे से आनन्द साउथ सिटी तक मार्ग की मरम्मत का कार्य।
12. वार्ड-70 पाल गैस गोदाम से ते-सेक्टर प्राइमरी पाठशाला होते हुये नाला रोड हाईटेन्शन रोड तक मार्ग की मरम्मत का कार्य। (शहरी मार्ग)
13. वार्ड-82 जरौली नाला रोड से आर0बी0एस0 स्कूल तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
14. जरौली फेस-1 में संतोष बाबा मन्दिर के सामने हरि नगर की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
15. वार्ड-52 रामगोपाल चौराहे से वरुण विहार तक मार्ग की मरम्मत का कार्य।
16. पटेल विहार वार्ड-82 की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
17. वार्ड-21 बजरंग विहार में विजय मेडिकल स्टोर से विनोद जैन के घर तक खाडेपुर नई बस्ती में रामपैलेस के बगल तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
18. वार्ड-87 राजेन्द्र नगर, आशा नगर व सरस्वती नगर की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
19. सजारी गाँव की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
20. सनिगवाँ मुख्य मार्ग से संदीप नगर में अन्ना चौराहा से कुसुम वाटिका होते हुये एस्सार पेट्रोल पम्प होते हुये दरियाव सिंह के घर से नितिन जनरल स्टोर होते हुये साँई चाट से रूपा सिंह साहू मन्दिर तक की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
21. सनिगवाँ मुख्य मार्ग से तिरंगा चौराहा होते हुये धीरेन्द्र शुक्ला के घर से रतन गुप्ता के घर होते हुये आलोक श्रीवास्तव के घर से चन्द्र प्रकाश पाण्डेय के घर बाबा टेण्ट हाउस होते हुये कबीर शाखा होते हुये मदरलैण्ड स्कूल से राधा माधव मन्दिर मुख्य मार्ग तक आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
22. वार्ड-21 योगेन्द्र विहार में हनुमंत गैस गोदाम के बगल से सविता सच्चान के घर होते हुये हंसवाहिनी स्कूल तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)

तकम में उपरोक्तानुसार सड़कों को लोक निर्माण विभाग, निर्माण खाण्ड-2 कानपुर नगर को हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा10 सदन के समक्ष रद्दीकृत/अनुमोदनाधी प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार 22 सड़कों को निर्माण/सम्मल कराये जाने के लिये नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदन भी प्रदान किया जा चुका है।

तदनुसार प्रथमतः उपरोक्तानुसार 22 सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री सीएम देव ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 305 के तहत किसी संस्था से दो वर्ष का अनुबंध किया जा सकता है, साथ ही कोई भी नीति निर्धारण समझौते परस्ताव सदन या कार्यकारिणी की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिये, जबकि अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य विल एवं लेखाधिकारी की कमेटी द्वारा सदन या कार्यकारिणी की सहमति आवश्यक न मानते हुये कतिपय विज्ञापन एजेन्सी से 25 वर्षों का 100पीपी0 मॉडल पर अनुबंध किया गया है। इस कृत्य से सदन का अपमान हुआ है, उस पर समन्वित दौबी अधिकारी के विकल्प कोई कार्यवाही होगी या नहीं? ऐसे निर्णयों से नगर निगम की छवि धूमिल होती है। अगर यह मामला मा10 न्यायालय में विचारणीय है, तो यह मामला मा10 न्यायालय में गया ही क्यों? अधिकारी इस पर बैठ कर बाल कर सकते थे। इसमें दक्षिणों पर सरल कार्यवाही की जाये। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय में। आपका ध्यान पालिका स्टैडियम के समन्वय में कीजा अधिकारी द्वारा आय-व्यय की जा ब्यारा उपलब्ध करवाया गया है, उसमें अनियमिततायें हैं। इनके द्वारा खर्चा रुपा 63,57,171 दिखाया गया है तथा 53 लाख रुपये धाटा दिखाया गया है। इनके द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में अलग जानकारी दी गयी और सदन में अलग। यदि नगर निगम ने पालिका स्टैडियम में किकेट प्रशिक्षण हेतु एन0एस0आई0कोष को रखा गया है और हम उसका प्रतिमाह रुपये 20,000/- सौलरी भी देते हैं, तो हम किकेट प्रशिक्षण हेतु अलग से कोष क्या दें? पालिका स्टैडियम में 05 बाबू है, परन्तु बुकिंग से लेकर अन्य समस्त कार्य एक ही व्यक्ति करता है। मैं भी अन्डर-19 का खिलाड़ी रहा हूँ। पालिका स्टैडियम में रु0 350 की बॉल से प्रैक्टिस होती है, वह बॉल में से पाया पड़ी है। उसकी कम्पनी से जांच करा ली जाये कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है? पालिका स्टैडियम में पदस्थ श्री जफर आलम, एन0एस0आई0 न्यायालय को निर्णय नहीं आता, तब तक श्री जफर आलम को सदन के माध्यम से कार्यभार क्या दिया जाये। इसी के साथ अपर नगर आयुक्त, प्रथम का यहाँ से स्थानान्तरण हो गया है, उन्हें भी सदन से कार्यभार क्या दिया जाये।

श्री आशिक गुप्ता ने कहा कि इस समन्वय में मामला न्यायालय में विचारणीय है, इस पर सदन को संज्ञान लेना उचित नहीं है।

हाजी सुहैल ने कहा कि किकेट एके डमी चलाये जाने के कार्यकारिणी समिति के निर्णय पर कोर्ट चले गये है, किस अधिकारी द्वारा जवाब दाखिल किया गया है? इसकी भी जाँच करायी जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि 25 वर्षों के अनुबन्ध की जाँच करायी जाये तथा पार्षदों की मांग को देखते हुए श्री जफर आलम को उनके पटल से कार्यमुक्त किया जाये।

श्री शिवम दीक्षित ने कहा कि नमामि गंगे के अधिकारी बिना क्षेत्रीय पार्षद को सूचित किये रात्रि में चोरी से जे0सी0बी0 लगाकर खुदाई कर देते और क्षेत्र की दर्दशा कर छोड़ देते है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन के माध्यम से उनको निर्देशित कर दिया जाये कि बिना पार्षद के संज्ञान में लाये क्षेत्र में खुदाई न की जाये। शक्करपट्टी, नयागंज, रामगंज में खुदाई कर दी गयी है, जल निगम के अधिकारी सुनते नहीं है, फोन पर अपशब्द से बात करते है।

जल निगम के अधिकारी ने अवगत कराया कि मा0 पार्षद जी के क्षेत्र में थोक एवं मुख्य बाजार है। जहाँ दिन में खुदाई करना सम्भव नहीं है, इस कारण से रात्रि में खुदाई करते है।

नगर आयुक्त ने कहा कि हम जल निगम को पत्र लिखकर यह कह रहे है कि किसी भी क्षेत्र में खुदाई करने से पूर्व हमें जानकारी दी जाये, ताकि तदनुसार माननीय पार्षदों को अवगत करा सके।

अध्यक्ष ने कहा परमट में भी बिना अनुमति के खुदाई की गयी है। सभी पार्षद शिकायत लिख कर दें, कार्यवाही करायी जायेगी, साथ ही जल निगम जहाँ पर भी कोई कार्य प्रारम्भ करें, हमें लिख कर दे, ताकि पार्षदों को अवगत कराया जा सके।

श्री यशपाल सिंह एवं श्रीमती नमिता मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रथम को 11 लाख, द्वितीय को रूपया 7.50 लाख तथा तृतीय को रूपया 05 लाख पुरस्कार पाने वाले में प्राप्त धन से विकास कार्य की बात कही गयी थी, जिसमें हमारे वार्ड सफाई में प्रथम व द्वितीय घोषित किये गये थे, किन्तु अभी तक प्रोत्साहन धनराशि से न तो कोई विकास हुआ और न ही कोई योजना बनी है?

सभापति ने कहा कि अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया है कि इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन धनराशि हेतु शासन को पत्र लिखकर भेजा गया था, किन्तु अभी तक शासन से धनराशि प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य नहीं कराये जा सके। शासन से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य कराये जायेंगे।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कृत वार्डों में नगर निगम निधि से विकास कार्य कराया जायेगा, शासन से प्राप्त होने पर नगर निगम निधि में समायोजित कर लिया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों द्वारा बुंदिया घाट की सीधियों पर मिट्टी भर कर घाट दिया गया है तथा घाट ही खत्म कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरी सीवर लाईन की गन्दगी सीधे गंगा में बहाई जा रही है। कौशिक पाक के अन्दर वर्ष 2007 में टंकी बनायी गयी है, किन्तु जल निगम एवं जलकल के बीच विवाद से पानी की सफाई आज तक नहीं हो पाई है। कृपया क्षेत्र में पानी की सफाई शीघ्र प्रारम्भ कराई जाये।

श्री मनोज राठौर ने कहा कि वाई-39 में जूही नहरिया से केनाल रोड में पिछले 06 माह से अस्वचार का फवारा फूटा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं किया गया है। टैरिन्ग के दौरान 07 लीकज को ठीक कर बनाया गया तो 20 लीकज हो गये। क्षेत्र की लगभग 80 हजार जनता पानी के तथे परेशान है, किन्तु जल निगम की लाईने अभी तक चालू नहीं है। जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। इसी शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये।

श्रीमती सीता पासवान ने कहा कि मेरे वाई-05 में लाईट जलती है, तो जलती रहती है और बन्द है तो बन्द है। जब इस सम्बन्ध में मार्ग प्रकाश के मुख्य अभियन्ता से शिकायत की जाती है, तो इनके द्वारा अपद्रव से बाल की जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। श्री अर्पित यादव एवं माँ0 आनिर ने कहा कि मार्ग प्रकाश विभाग में अनेकों अनियमितारों की जा रही है, लाईट नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में प्रमारी मुख्य अभियन्ता (मार्ग प्रकाश) से शिकायत करने पर उनके द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं दिया जाता है। प्रमारी अधिकारी (मार्ग प्रकाश) ने आश्चर्य किया कि पार्श्वों की जो भी लाईट की मांग होगी, उसे पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष ने सम्स्त अधिकारियों को निर्दिष्ट किया कि पार्श्वों का काम हो या न हो, किन्तु सभी अधिकारी पार्श्वों से सम्मानजनक ढंग से बात करें, साथ ही अवगत कराया कि बागड़ी में सीवर भरव की काफी समस्या है, जनता परेशान है, क्षेत्र की पार्श्व मुझसे मिली थी। से बाल करें, साथ ही अवगत कराया कि बागड़ी में सीवर भरव की काफी समस्या है, जनता परेशान है, क्षेत्र की पार्श्व मुझसे मिली थी। कल अपराह्न 01:00 बजे में सन्तुलित स्थल पर जाऊँगी, अधिकारी मौजूद रहें। जिन पार्श्वों के यहाँ सफाई कमियाँ की संख्या कम है, वे अवगत कराये, तदनुक्रम में निम्नवत सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया :-

वाई सी0	सफाई कमियों की सी0	वाई सी0	सफाई कमियों की	वाई सी0	सफाई कमियों की
109	34	84	39	83	38
45	37	54	34	87	39
27	37	88	37	55	35
25	32	36	15	09	39
23	28	67	36	90	39

श्री संजय यादव ने कहा कि महाबलीपुरम कानपुर नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है, किन्तु वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, जिससे जनता परेशान है, जाँच कराकर विकास कार्य कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि पार्श्वदो के टैक्स के सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करें, किस आधार पर कर निर्धारण किया जा रहा है, जब मकान का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, तो किस आधार पर टैक्स कई गुना बढ़ रहा है। शीत ऋतु चल रही है, अलाव जलाने हेतु गीली लकड़ी किसके माध्यम से ली गयी, गीली लकड़ी जलाने के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था। मैंने जोनल अभियन्ताओं को मीटिंग के लिये बुलाया था, जिसमें सिर्फ 02 जोनल अभियन्ता ही उपस्थित हुये, बाकी जो-1 के जोनल अभियन्ता अस्वस्थता के कारण, अन्य 03 अभियन्ता विभिन्न कारणों से बाहर थे, अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि अधिकारी जब भी छुट्टी पर जाते हैं, तो वह नगर आयुक्त की जानकारी में तो देते ही हैं, उसे मेरे संज्ञान में भी लाया जाये। पिछली कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पार्किंग स्थल पर पार्किंग से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को अंकित करते हुये बोर्ड लगवाया जाये। सदन में उपस्थित जोनल अधिकारी यह बताये कि उनके जोनों में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी।

जोनल अधिकारी ने अवगत कराया कि हमारे द्वारा कई स्थानों पर बोर्ड तो लगवाये गये, किन्तु सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा उन्हें तुड़वा दिया गया।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि यदि किसी ठेकेदार द्वारा नगर निगम का लगवाया गया बोर्ड तोड़ा जाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार को चिन्हित करते हुये उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। यदि कोई ठेकेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पार्किंग शुल्क वसूली करता है, तो उसका ठेका निरस्त किया जाये। चट्टे के अभियान में मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, सर्दी के कारण मैं एक सप्ताह उपरान्त अभियान चलाऊँगी। चट्टा महानगर के लिये नासूर है, उसे अवश्य हटवाया जायेगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि 600 कूड़ा गाड़ियों की और खरीद होनी है 01-01 वार्ड में 05 से 06 गाड़ियाँ उपलब्ध हो जायेंगी, जिससे कूड़ा उठान हो सकेगा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मुख्य अभियान्ता द्वारा सदन के सुन्दरीकरण, माईक सिस्टम को ठीक कराने में लगभग रूपया 57 लाख का व्यय नगर निगम द्वारा किया गया है, फिर भी सदन का साउन्ड सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है, इसकी जाँच कराते हुये अगले सदन से पूर्व साउन्ड सिस्टम ठीक कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाये।

अध्यक्ष/सहाय
(प्रतिलिपि पाठ्य)
.....

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि बरसात ज्यादा होने के कारण संगम ताल तिरह से काहू कोठी होते हुये नयानां तक सड़क कार्यों को तत्काल करवा जा सके।

श्री अमीम ने कहा कि अभियान विभाग के डम्पों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये, जिससे आकस्मिक कार्यों में पैच, मरम्मत अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है, उबल मार्ग से रामनवमी, गणेशोत्सव का देला व अन्य कई शीमायाजाये निकलती है, सड़क खराब होने के कारण कभी-कभी बड़ी असहज स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मा० अध्यक्ष महोदय सन्तुष्ट सड़क का निर्माण कराया जाने हेतु आप द्वारा निर्देशित किया गया था, किन्तु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा आज तक पत्रावली तैयार कर उबल अधिकारियों तक प्रेषित नहीं की गयी है, यदि जो अवर अभियन्ता कार्य नहीं करना चाहते है, उनको कार्यमुक्त किया जाये।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सम्बन्धित यात्रा मार्ग की पत्रावली तैयार कर तत्काल सड़क बनायी जाये।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से पूर्व पर्वत ओम प्रकाश गान्धीकी के निधन पर दो मिनट का मौन रखने हेतु कहा, जिस पर सदन समगार में उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु प्रार्थना की गयी।

अध्यक्ष ने सदन समगार में उपस्थित सभी सदस्यों से आज दिनांक 08.01.2020 दिन बुधवार को सम्मन हुई बैठक की कार्यवाही की प्रार्थना की गयी।

श्री अमीम ने कहा कि अभियान विभाग के डम्पों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये, जिससे आकस्मिक कार्यों में पैच, मरम्मत अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है, उबल मार्ग से रामनवमी, गणेशोत्सव का देला व अन्य कई शीमायाजाये निकलती है, सड़क खराब होने के कारण कभी-कभी बड़ी असहज स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मा० अध्यक्ष महोदय सन्तुष्ट सड़क का निर्माण कराया जाने हेतु आप द्वारा निर्देशित किया गया था, किन्तु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा आज तक पत्रावली तैयार कर उबल अधिकारियों तक प्रेषित नहीं की गयी है, यदि जो अवर अभियन्ता कार्य नहीं करना चाहते है, उनको कार्यमुक्त किया जाये।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सम्बन्धित यात्रा मार्ग की पत्रावली तैयार कर तत्काल सड़क बनायी जाये।

अध्यक्ष ने सदन समगार में उपस्थित सभी सदस्यों से आज दिनांक 08.01.2020 दिन बुधवार को सम्मन हुई बैठक की कार्यवाही की प्रार्थना की गयी।

श्री अमीम ने कहा कि अभियान विभाग के डम्पों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये, जिससे आकस्मिक कार्यों में पैच, मरम्मत अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है, उबल मार्ग से रामनवमी, गणेशोत्सव का देला व अन्य कई शीमायाजाये निकलती है, सड़क खराब होने के कारण कभी-कभी बड़ी असहज स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मा० अध्यक्ष महोदय सन्तुष्ट सड़क का निर्माण कराया जाने हेतु आप द्वारा निर्देशित किया गया था, किन्तु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा आज तक पत्रावली तैयार कर उबल अधिकारियों तक प्रेषित नहीं की गयी है, यदि जो अवर अभियन्ता कार्य नहीं करना चाहते है, उनको कार्यमुक्त किया जाये।